जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 64278/96 वर्ष:29 अंक: 105 दिनांक:18-08-2024 रविवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 वडोदरा M

बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने पड़ोसी देश में कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार एवं हत्या के विरोध में जारी प्रदर्शनों में शामिल होकर एकजुटता दिखायी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया कि आज सुबह 02:35 बजे साबरमती एक्सप्रेस का इंजन ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराया और कानपुर के पास पटरी से उतर गया। इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह क्षतिग्रस्त/मुड़ा हुआ था।

लीपापोती और धरना-ड्रामा, यही ममता सरकार की एबीसीडी

-बीजेपी प्रवक्ता पूनावाला ने ट्रेनी डॉक्टर हत्याकांड पर टीएमसी को घेरा

नई दिल्ली,(ईएमएस)। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले दिनों हमने एक भयानक रेप और हत्या देखी। हर कोई गुस्से में है- चाहे वह डॉक्टर हों या महिलाएं। सभी लोग सड़क पर हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं बंगाल सरकार ने अस्पताल से 42 डॉक्टरों का तबादला कर दिया है।

पूनावाला ने कहा कि न्याय देने के बजाय सरकार का एजेंडा बलात्कारी को बचाने के लिए न्याय नहीं देना है। उन्होंने उस सीमा को पार कर लिया है, जहां उन्हें तानाशाही मुझे चाहिए संस्कृति का प्रचार करने वाली पार्टी कहना सही होगा। ममता को किम जोंग उन और स्टालिन जैसे बड़े से बड़े तानाशाह भी आश्चर्य से देखेंगे। पिछले दो दिनों में जो कोई भी सोशल मीडिया पर बेटी के लिए बोल रहा है, कोलकाता पुलिस उन्हें ट्वीट हटाने के लिए पत्र भेज रही है। इससे आप कोलकाता पुलिस की प्राथमिकता देख सकते हैं।

पूनावाला ने कहा कि ममता बनर्जी में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। अपराधी बचाओ, बाम और राम को कोसना, हिंदू विरोधी मानसिकता, लीपापोती और धरना-ड्रामा, यही ममता सरकार की एबीसीडी है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी कहां हैं, कहां हैं फासीवाद मुर्दाबाद के नारे। वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष पूछताछ के लिए शनिवार को सीबीआई के सामने पेश हुए। घोष दूसरी बार पूछताछ के लिए शनिवार को सीबीआई कार्यालय पहुंचे। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के पहले दौर में घोष से महिला ट्रेनी डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया।

अमित शाह ने कहा - बीजेपी 35 साल तक और सत्ता में रहेगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 35 साल तक और सत्ता में रहेगी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे।

शाह ने कहा कि बीजेपी की जड़ें मजबूत हैं, संगठन मजबूत हैं। बीजेपी जहां सत्ता में है। वहां से जाती नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जहां जाती है फिर वहां आती नहीं। बता दें कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। इसके बाद बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने की हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील

-सुरक्षा को लेकर कमेटी गठन का किया वादा

नई दिल्ली (ईएमएस)। कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने शनिवार को देशभर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 24 घंटे हड़ताल बुलाई है। आईएमए ने कहा कि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और कैजुअल्टी वॉर्ड चालू रहेगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने व्यापक जनहित में तथा डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखकर आंदोलनकारी डॉक्टरों से अपनी डयूटी पर लौटने का अनुरोध किया है। अभी तक डॉक्टरों की ओर से अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित होगी।

कोलकाता में 8 और 9 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर से हुई बर्बरता और हैवानियत के बाद इंसाफ और न्याय की गूंज देश के हर कोने में और तेज होती जा रही है। शहर-शहर, सड़क-सड़क डॉक्टर अपने साथी के साथ रेप और हत्या के बाद इंसाफ मांग रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर के बलात्कार और हत्या तथा उसके बाद हुई तोड़फोड़ के विरोध में शनिवार को देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है।

सिद्धारमैया के खिलाफ चलेगा केस, राज्यपाल के फैसले को दी जाएगी कानूनी चुनौती

बेंगलुरु (ईएमएस)। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित मुदा घोटाले में मुकदमा चलाने की अनुमति देने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा पूरे मामले में जबरदस्त तरीके से हमलावर है। हालांकि, पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि पूरा मंत्रिमंडल, पार्टी हाईकमान, सभी विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के राज्यपाल का फैसला संविधान विरोधी और कानून के खिलाफ है। राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी।

वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का भी बयान सामने आया है। डीके ने कहा कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक और कानून के खिलाफ है। सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है। वे (बीजेपी) राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मेरे सीएम किसी दबाव में नहीं आएंगे। उनके इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है। हम सब एकजुट हैं, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है।

सीएम का बचाव कर डीके ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ भी गलत नहीं किया है। यह पूरी तरह से एक राजनीतिक मुद्दा है। राज्यपाल के कार्यालय का इस बीजेपी सरकार द्वारा दुरुपयोग किया गया है...हम इसके खिलाफ कानूनी तरीके से लड़ने को तैयार है। हमें इस देश के कानून पर पूरा भरोसा है और मेरी सरकार की रक्षा होगी। उन्होंने कहा कि हम सीएम सिद्धारमैया के साथ खड़े हैं। पार्टी, हाईकमान और पूरा राज्य और मंत्रिमंडल उनके साथ खड़ा है। जो भी नोटिस और मंजूरी दी गई है, वह कानून के खिलाफ है। हमने कानूनी तौर पर इसका मुकाबला करने की पूरी तैयारी कर ली है, यह पिछड़े वर्ग के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ एक स्पष्ट साजिश के अलावा और कुछ नहीं है, जो दूसरी बार सरकार चला रहे हैं।

दरअसल राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसुरू शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन 'घोटाले' के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। राजभवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला टी जे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा की ओर से दायर तीन अर्जी पर आधारित है।''

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मौसम विभाग की चेतावनी ने बढ़ाई चिंता

नई दिल्ली(ईएमएस)। देश के कई राज्यों में इन दिनों तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। भारत के मौसम विभाग ने भी इस वर्ष सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया है। इसी बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार रिकॉर्ड बारिश होगी। देश में ज्यादा बारिश खेती-किसानी और जन जीवन के लिए आफत बनेगी। इस चेतावनी के बाद किसान सबसे अधिक चिंतित हैं। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 2015-2021 के बीच ज्यादा बारिश होने से करीब 34 मिलियन हेक्टेयर में फसलों को नुकसान हुआ है। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई जब देश में एक जून से अब तक सामान्य से 5 फीसदी बारिश हो रही है। ऐसे में ये सवाल फिर उठ रहा है कि क्या इस बार भी ज्यादा बारिश से नुकसान होगा या नहीं?

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्व में हुई अधिक बारिश से भारत में फसलों को नुकसान हुआ है। देश में करीब 40 फीसदी आबादी खेती और उससे जुड़े संसाधनों पर निर्भर है। 2015 से 2021 के बीच 33.9 मिलियन हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ। जबकि सूखे के कारण 35 मिलियन हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई। देश में 2021 में 159 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था।

सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को सूखे से

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि, तेज बारिश और बाढ़ के मुकाबले सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को सूखे से होता है। जब भी ज्यादा बारिश होती तो इससे रबी की फसलों को ज्यादा फायदा होता है। ज्यादा बारिश और ज्यादा सूखा में से अक्सर ज्यादा सूखा ही किसानों के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक नुकसानदेह होता है, क्योंकि बारिश का प्रभाव कुछ दिनों तक ही रहता है। वहीं, सूखे का प्रभाव लंबी अवधि तक रहता है। वहीं, जिस साल ज्यादा बारिश होती है उस साल अक्सर रबी की फसल अच्छी रहती है। ऐसे में किसानों को काफी हद तक नुकसान की भरपाई हो जाती है।

अगले हफ्ते तेज वर्षा

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल पर कम दबाव का क्षेत्र बना है जिसके और संघटित होने की संभावना है। इसके प्रभाव से अगले सप्ताह के दौरान पूर्वी और मध्य भारत में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा, अगले 2-3 दिनों के दौरान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, 20 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में व्यापक रूप से हल्की/मध्यम वर्षा हो सकती है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भी छिटपुट से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है।

भारत लाया जा सकता है 26/11 का आतंकी तहव्वुर राणा

-अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज की

भोपाल(ईएमएस)। 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ उसकी अपील को अमेरिकी अदालत ने खारिज कर दिया है। अमेरिकी अदालत ने 15 अगस्त को अपने फैसले में कहा कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है।

पाकिस्तानी मूल के कनाडाई बिजनेसमैन राणा ने नाइंथ सर्किट कोर्ट में पिछले साल एक याचिका दायर की थी। उसने गुहार लगाई थी कि सुनवाई तक उसे भारत को न सौंपा जाए। मई 2023 में भी एक अमेरिकी अदालत ने राणा की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। भारत को सौंपे जाने से बचने के लिए पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा ने अमेरिका की कोर्ट में हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर की थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में रखा जाए। हालांकि लॉस एंजिलिस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जिन आरोपों को आधार बनाकर भारत ने तहव्वुर के प्रत्यर्पण की मांग की है, उन्हें देखते हुए उसके प्रत्यर्पण की इजाजत दी जा सकती है। अपने खिलाफ फैसला आने के बाद राणा ने नाइंथ सर्किट कोर्ट में एक और याचिका दायर की थी।

हरियाणा में चुनाव से पहले जजपा को बड़ा झटका

चंडीगढ़(ईएमएस)। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, सूबे में 1 अक्टूबर को एक ही फेज में 90 सीटों पर चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। चुनाव के ऐलान के साथ ही जननायक जनता पार्टी (जजपा) में भगदड़ मची हुई है। जजपा से पिछले 2 दिन में 4 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसमें ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली, अनूप धानक और राम करण कला का नाम शामिल है।

बता दें कि हरियाणा के टोहाना से जेजेपी विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने आज पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दिया है, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अजय चौटाला को एक पत्र के जरिए अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एक दिन पहले ही पार्टी के एक और विधायक और पूर्व मंत्री अनूप धानक ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही रामकरण काला ने भी पार्टी छोड़ दी है।

कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी

कानपुर(ईएमएस)। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस (19168) पटरी से उतर गई। 22 डिब्बे डिरेल हुए हैं। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कुछ यात्री घायल हुए हैं। हादसा देर रात 2.35 बजे कानपुर शहर से 11 किमी दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुआ।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी भारी चीज से टकराया। इंजन पर टकराने के निशान हैं। सबूत सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस जांच कर रही है। नॉर्दन सेंट्रल रेलवे के जीएम उपेंद्र चंद्र जोशी ने कहा- यह तय है कि हादसा इंजन के किसी चीज से टकराने से हुआ है। मौके पर कोई चीज नहीं मिली है। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 70 से 80 के बीच थी।

एक पहिया उतरते ही प्रेशर कम हुआ। ड्राइवर ने वक्त रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। रेल अफसरों ने बताया कि हादसे से 1 घंटे 20 मिनट पहले पटना-इंदौर एक्सप्रेस ट्रैक से गुजरी थी, तब तक ट्रैक सुरक्षित था। हादसे के बाद 16 ट्रेनों को रद्द किया गया। 10 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। रेलवे का कहना है कि 24 घंटे में ट्रैक क्लियर कर देंगे।

कानपुर रेल हादसे में साजिश की बू, साबर-मती डिरेल होने की आईबी करेगी जांच

कानपुर (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शनिवार तड़के एक बड़ा रेल हादसा टल गया। कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन संख्या 19168, साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इंजन ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराया और कानपुर के पास पटरी से उतर गया। फिलहाल घटनास्थल से किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। यात्रियों को कानपुर ले जाने के लिए बसें मौके पर पहुंचीं और यात्रियों को कानपुर ले गईं। आईबी और यूपी पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच में जुटी है।

जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 19168, साबरमती एक्सप्रेस आज सुबह 02:35 बजे कानपुर के पास पटरी से उतर गई। इंजन ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकरा गया और पटरी से उतर गया। लोको पायलट के अनुसार, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बोल्डर इंजन से टकराया था, जिसके कारण इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह क्षतिग्रस्त-मुड़ा हुआ था। साक्ष्य सुरक्षित रखे गए हैं, जो लोको से 16वें कोच के पास मिले हैं। शुरुआती जांच के अनुसार, रेलवे ट्रैक में कोई फ्रैक्चर नहीं है। आईबी और यूपी पुलिस की इस पर भी नजर है। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है। यात्रियों के लिए अहमदाबाद की आगे की यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है। भारतीय रेलवे ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

रेलवे डीआरएम झांसी डिवीजन दीपक कुमार ने कहा कि इस घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। यात्रियों को बस और ट्रेन के माध्यम से कानपुर वापस ले जाया गया है। यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए कानपुर में एक और ट्रेन तैयार की गई है। उधर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया कि आज सुबह 02:35 बजे साबरमती एक्सप्रेस (वाराणसी से अमदावाद) का इंजन ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराया और कानपुर के पास पटरी से उतर गया। इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह क्षतिग्रस्त-मुड़ा हुआ था। साक्ष्य सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है।

देश की आत्मा पर हमला......3 याचिकाएं पहुंचीं सीजेआई चंद्रचूड़ के पास

ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला

कोलकाता (ईएमएस)। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंच गया है। सीजेआई को तीन पत्र याचिका भेजी गई हैं जिसमें आर्मी कॉलेज के एक डॉक्टर की भी याचिका शामिल है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सीजेआई इस भयानक घटना का स्वतः संज्ञान लें और तेज कार्रवाई के निर्देश दें।

इसमें दो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के ही वकील रोहित पांडेय और उज्ज्वल गौड़ हैं। तीसरी याचिकाकर्ता का नाम डॉ. मोनिका सिंह हैं जो कि आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल, सिकंदराबाद में बीडीएस हैं। वहीं पांडेय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव हैं। गौड़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य हैं।

सुप्रीम कोर्ट के वकील पांडेय और गौड़ ने कहा कि यह केस बहुत ही भयानक और दुर्लभ है। यह हमारे देश की आत्मा पर अत्याचार है। एक डॉक्टर पर ही नहीं बल्कि मानवता पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि सीजेआई चंद्रचूड़ को मामले में उचित निर्देश देने की जरूरत है। याचिका में कहा गया है कि इस बर्बर घटना ने पूरे देश की आत्मा को हिला दिया है। पीड़िता के रोते बिलखते परिवार को देखकर हर किसी की दिल पसीज जाता है। हालांकि घटना के बारे में बोलने के लिए ज्यादा शब्द नहीं हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमें खड़े होना चाहिए और मामले में तीव्र जांच और न्याय सुनिश्चित होना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि इस तरह की बर्बर घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एक महिला के आत्मसम्मान और कानून की रखवाली के लिए भी एक्शन जरूरी है। डॉ. सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि सीजेआई चंद्रचूड़ को मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर भी न्यायालय को उचित निर्देश देने चाहिए। अस्पतालों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की जरूरत है।

बता दें कि कोलकाता के अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बर रेप कर फिर हत्या की गई। इस घटना के बाद पूरे देश में उबाल है।

सरकार के लिए सेबी प्रमुख माधवी बुच को बचाना नामुमकिन

- हर्षद मेहता, केतन पारेख और अब अदानी की जेपीसी जांच?

नई दिल्ली (ईएमएस)। बाजार नियामक आयोग सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उनको बचा पाना शायद इस बार सरकार के लिए संभव नहीं होगा। हिडनबर्ग ने जो आरोप तथ्यों और दस्तावेजों के साथ सार्वजनिक किए हैं। उसका जवाब अभी तक सेबी प्रमुख नहीं दे पाई हैं। सेबी प्रमुख के पद पर रहते हुए, कंसल्टेंसी फर्म एगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में माधवी बुच की हिस्सेदारी 99 फ़ीसदी है। उसमें उन्होंने 3.71 करोड रुपए की कमाई की है,यह प्रमाणित है। इससे बच पाना माधवी बुच के लिए संभव नहीं रहा। भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव और उनके कार्यकाल मे सेबी बोर्ड के सदस्य सुभाष चंद्र गर्ग ने स्पष्ट किया है। सेबी नियमों के अनुसार यह एक गंभीर उल्लंघन है। सेबी का सदस्य बनते ही उन्हें मालिकाना हक जारी रखने का कोई अधिकार नहीं था। 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार वह 99 फ़ीसदी हिस्सेदारी की मालिक हैं। उन्होंने सेबी के नियमों का स्वयं उल्लंघन किया है। जो सेबी प्रमुख को पद से उन्हें अयोग्य बनाता है। यह मामला अब इतना तूल पकड़ चुका है। इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो भारत में निवेश करने से अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भागने लगेंगे। देश और विदेश में यह संदेश जा रहा है। सेबी निष्पक्षता के साथ नियमो और कानून का पालन नहीं कराती है। सेबी प्रमुख करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष की कमाई सिंगापुर में रहते हुए कर रही थी। उन्होंने मात्र 36 लाख रुपए वार्षिक की नौकरी क्यों स्वीकार की। हिडनबर्ग ने जो जानकारी सार्वजनिक की है। उसके बाद यह राज भी खुल गया है। उनके संबंध अदानी समूह से हैं। हिडनवर्ग की रिपोर्ट के बाद माधवी बुच के साथ-साथ अदानी के कारोबार को भी प्रभावित करने वाले होंगे।

ओपिनियन पोल में हरियाणा में किसी को बहुमत नहीं

चंडीगढ़ (ईएमएस)। चुनावी शेडयूल जारी होते ही हरियाणा का एक ओपिनियन पोल सामने आया है। इस सर्वे में किसी भी दल को पिछली बार की तरह ही बहुमत मिलता नहीं दिखाया गया है। हालांकि, इस बार करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है।

टाइम्स नाऊ और मैटराइज के सर्वे के अनुसार, बीजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा 35.2 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 31.6 प्रतिशत, जेजेपी को 12.4 प्रतिशत और अन्य को 20.8 प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है। हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 है, लेकिन किसी भी दल को इतनी सीटें मिलती नहीं दिख रहीं। सर्वे के अनुसार, बीजेपी गठबंधन को 37-42, कांग्रेस को 33-38, जेजेपी को तीन से आठ और अन्य को सात से 12 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि इस बार फिर से जेजेपी के दुष्यंत चौटाला की सरकार बनाने में अहम भूमिका हो सकती है।

गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट दिसंबर में

जी1 रॉकेट के हार्डवेयर श्रीहरिकोटा पहुंचे, त्रिवेंद्रम में क्रू-मॉडयूल पर काम जारी

बेंगलुरु(ईएमएस)। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट इस साल दिसंबर में लॉन्च करेगा। इसमें इंसान को नहीं भेजा जाएगा। मिशन की दूसरी फ्लाइट में रोबोट व्योम मित्र और तीसरी उड़ान में चार अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। इसरो ने अभी दूसरी और तीसरी उड़ान का समय नहीं बताया है।

इसरो चेयरमैन एस. सोमनाथ ने बताया कि मिशन के रॉकेट के हार्डवेयर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं। वहीं त्रिवेंद्रम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में क्रू-मॉडयूल पर काम जारी है। उम्मीद है कि नवंबर तक यह काम पूरा हो जाएगा। गगनयान का मानव मिशन 3 दिनों का होगा, जिसके तहत एस्ट्रोनॉट्स के दल को 400 किमी ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद क्रू मॉडयूल (जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठते हैं) को सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराया जाएगा। भारत इस मिशन में कामयाब रहा तो वह ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ऐसा कर चुके हैं।

ग्रैंड वेलकम देख इमोशनल हुईं विनेश फोगाट

उन्होंने गोल्ड नहीं दिया तो क्या...अपनों से जो प्यार और सम्मान मिला है वो हजारों गोल्ड मेडल के आगे फीके हैं

बादली / हरियाणा (ईएमएस)। स्टार भारतीय रेसलर विनेश फोगाट शनिवार को पेरिस से भारत लौट आईं। विनेश का दिल्ली एयरपोर्ट पर विनेश का जोरदार स्वागत हुआ। विनेश को रिसीव करने स्टार रेसलर्स बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे थे। विनेश अब दिल्ली से अपने पैतृक गांव बलाली गई हैं। बलाली जाने के क्रम में जगह-जगह विनेश का ग्रैंड वेलकम हुआ।

हरियाणा के बादली में भी लोगों ने विनेश फोगाट का शानदार स्वागत किया। इस दौरान विनेश फोगाट ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जितने भी लोग स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने हमें गोल्ड मेडल नहीं दिया तो क्या हो गया। हमारे अपनों ने हमें गोल्ड से भी ऊपर नवाजा है। ये मान सम्मान हजारों गोल्ड मेडल के आगे फीके हैं।

बादली में पहुंची विनेश फोगाट ने मंच पर माइक लेकर लोगों के बीच अपने मन की बात रखी। उन्होंने कहा कि कल तक मैं खुद को कोस रही थी, लेकिन आज मैं कह सकती हूं कि मुझसे खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान हर घर में बच्चे का नसीब मेरे जैसा लिखे, जिसे देश में इतना मान सम्मान मिलता हो। वही विनेश ने मंच से एक वादा किया कि वह अपनी लड़ाई जारी रखेगी और कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों का सिर नहीं झुकने देगी। विनेश ने कहा कि उन्होंने गोल्ड नहीं दिया तो क्या हुआ लेकिन जो आज देश का प्रेम मिल रहा है वह गोल्ड से कई ज्यादा है। वही बजरंग पूनिया ने भी कहा कि विनेश फोगाट गोल्ड नहीं डायमंड है।

विनेश ने दिए रिटायरमेंट से वापसी के संकेत

विनेश ने डिस्क्वालिफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। हालांकि उन्होंने अब रिटायरमेंट से वापसी के संकेत दिए। विनेश ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि हो सकता है कि अलग-अलग परिस्थितियों में, मैं खुद को 2032 तक खेलते हुए देख सकूं, क्योंकि मेरे अंदर संघर्ष और कुश्ती हमेशा रहेगी। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि भविष्य में मेरे लिए रखा है लेकिन मुझे इस यात्रा का इंतजार है। मुझे यकीन है कि मैं जिस चीज में विश्वास करती हूं और सही चीज के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी।

15 हजार फुट की ऊंचाई पर 'क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय वायुसेना और थलसेना ने संयुक्त रूप से लगभग 15 हजार फुट की ऊंचाई पर 'आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब पहल के तहत ''अपनी तरह के पहले सटीक पैरा-ड्रॉप अभियान को अंजाम दिया है। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी।मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन 'क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब को परियोजना भीष्म यानी सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल के अंतर्गत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।

इस अभियान को मानवीय सहायता और आपदा राहत के रूप में प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप अंजाम दिया गया। बयान में कहा गया कि वायुसेना ने क्यूब को 'एयरलिफ्ट करने और सटीक रूप से 'पैरा-ड्रॉप करने के लिए अपने उन्नत सामरिक परिवहन विमान सी-130जे सुपर हरक्यूलिस का इस्तेमाल किया।

इसमें कहा गया कि थलसेना की पैरा ब्रिगेड ने अपने उन्नत सटीक ड्रॉप उपकरणों का इस्तेमाल करके 'ट्रॉमा केयर क्यूब की सफल तैनाती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रदर्शन ने दूरदराज के और पर्वतीय क्षेत्रों में भी मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में प्रभावी ढंग से सहयोग को लेकर ऐसी विशेष सैन्य क्षमता को रेखांकित किया।

भीष्म ट्रॉमा केयर क्यूब के सफल पैरा-ड्रॉप अभियान और तैनाती ने सशस्त्र बलों के बीच बेहतर तालमेल का उदाहरण तथा सबसे पहले, समय पर और प्रभावी सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

उदयपुर में चाकूबाज के घर चला बुलडोजर, आरोपी किरायेदार निकला.....अब प्रशासन पर सवाल

-बच्चे की हालात में सुधार

उदयपुर,(ईएमएस)। राजस्थान के उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव के बाद, अधिकारियों ने अपने सहपाठी पर हमला करने वाले चाकूबाज के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। इसके बाद लोगों ने बताया कि आरोपी और उसका परिवार तो उस मकान में किराये से रहता था। इस पर स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि बेकसूर के मकान को तोड़कर सरकार क्या जतलाना चाह रही है? वहीं दूसरी तरफ घायल हुए बच्चे की हालत में सुधार बताया गया है।

जिसे लेकर यह सब हुआ उस झगड़े का कारण अज्ञात था, लेकिन घटना ने सांप्रदायिक झड़पों को भड़का दिया, जिससे अधिकारियों ने शहर में धारा 144 लागू कर दी। यह घटना भट्टियानी चोहट्टा के एक सरकारी स्कूल में हुई, जहाँ कक्षा 10 के एक छात्र ने दूसरे लड़के को चाकू मार दिया। हालाँकि झगड़े का तात्कालिक कारण अभी भी जांच के दायरे में है, लेकिन पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद पूरे शहर में हिंसा भड़क उठी, गुस्साई भीड़ ने पथराव कर तीन या चार कारों को आग लगा दी।

वहीं उदयपुर कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि बच्चे को उचित इलाज मिले। बच्चे की हालत में सुधार है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अफवाह न फैलाएं। आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, ताकि पता लग सके कि उनके पास अवैध हथियार कहां से आए। दो बच्चों के बीच हुई झड़प के बाद शहर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उदयपुर जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी है।

उदयपुर शहर, बेदला, बड़गांव, ब्लीचा, देबारी, एकलिंगपुरा, कानपुर, ढीकली और भुवाना क्षेत्र में शुक्रवार रात 10 बजे से 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। जिलाधिकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीन चिकित्सकों की टीम विशेष विमान से जयपुर से उदयपुर आ रही है। उन्होंने बताया कि घायल छात्र की हालत स्थिर है। पोसवाल ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।

जन हितैषी

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में

निर्वाचन आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा की चुनाव अधिसूचना जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव होंगे। अनुच्छेद 370 खत्म होने और जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासन के अधीन घोषित होने के बाद यह पहला चुनाव है। इस चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर के नेता कई महीनो से इंतजार कर रहे थे। यहां की जनता भी चुनाव नहीं होने से नाराज थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आखिरकार यहां पर चुनाव आयोग को चुनाव कराना पड रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। वहीं हरियाणा में एक चरण में चुनाव संपन्न होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 90-90 सीटें हैं। कहने का तात्पर्य यह है, दोनों विधानसभाएं छोटी हैं। जम्मू- कश्मीर में आतंकवादियों के हमले हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग ने तीन चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के संबोधन में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही थी। जब चुनाव आयोग चार राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकता है। तब प्रधानमंत्री कैसे एक साथ सभी चुनाव एक साथ कराने की बात कर रहे हैं। कई राज्यों में 46 सीटों पर उपचुनाव होने थे, चुनाव आयोग द्वारा कोई उपचुनाव नहीं कराये जा रहे हैं। 10 विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हैं। सीमावर्ती राज्य हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। तब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव कराने मैं क्या दिक्कत थी। इसे आसानी से समझा जा सकता है। वायनाड की लोकसभा सीट के चुनाव बाद में भी कराये जा सकते थे। जिन राज्यों में अनुकूलता थी, वहां पर उपचुनाव नहीं कराने से चुनाव आयोग के निर्णय पर तरह-तरह की शंका पैदा की जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था। जो शिकायतें की गई थी, उनका निराकरण नहीं किया गया। किस राज्य में और किस संसदीय क्षेत्र में कितना मतदान हुआ है। उसमें विलंब होना, बाद में मतदान की संख्या में भारी अंतर को लेकर, चुनाव आयोग के ऊपर तरह-तरह के आरोप लगे। एडीआर द्वारा लोकसभा चुनाव की जो जानकारी मांगी गई, वह चुनाव आयोग द्वारा नहीं दी जा रही है। चुनाव आयोग पहले ही कटघरे में खड़ा था, अब उपचुनाव नहीं कराने तथा केवल दो राज्यों के चुनाव कराने को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं। यह भी कहा जा रहा है, दिल्ली विधानसभा के चुनाव समय के पहले हो सकते हैं। दिल्ली में चुनाव की तैयारी चुनाव आयोग द्वारा शुरू कर दी गई है। जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के चुनाव संपन्न हो जाने के बाद महाराष्ट्र के साथ दिल्ली और झारखंड के चुनाव होंगे। इसकी अटकलें शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग की जितनी आलोचना 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई है। उसके पहले कभी भी चुनाव आयोग को लेकर इस तरह की आलोचना नहीं हुई थी। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलते नहीं हैं। मीडिया से भी दूरी बनाकर रखते है। चुनाव आयोग के कार्यों में पारिदर्शिता नहीं है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता आम मतदाताओं के बीच में कम होना चिंता का विषय है। लोकसभा चुनाव के पहले भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कई आंदोलन हुए। लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद जिस तरह की शंका चुनाव आयोग के प्रति की जा रही है। जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं। उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। अब तो चर्चा यह भी होने लगी है, चुनाव आयोग में भारी भ्रष्टाचार है। चुनाव के दौरान जो खर्च किया जाता हैं। उनका केंद्रीकरण कर दिया गया है। मनमाने तरीके से काम कराए जाते हैं। मनमाने तरीके से भुगतान किया जाता है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसलिए उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं होती है। जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं। आयोग सत्तारूण दल के इशारे पर काम करने का आरोप लग रहा है। ऐसे समय पर चुनाव आयोग को पारिदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम करने की जरूरत है। जब तक आम मतदाताओं को चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास है। तभी तक लोकतंत्र और चुनाव के माध्यम से बनी हुई सरकारें सुरक्षित हैं। जिस दिन जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। उस दिन चुनाव आयोग और चुनाव के माध्यम से चुनी गई सरकारों का भी भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता जरूरी है। आशा है चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा।

अंततः अखंड भारत का सपना होगा साकार

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त 2024 को पूरे भारतवर्ष में 77वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूम धाम से मनाया गया। दरअसल, भारतीय नागरिक 15 अगस्त 1947 के पूर्व अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत पराधीन थे एवं 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के शासन से मुक्त होकर भारतीय नागरिक स्वाधीन हुए। इसलिए इस पर्व को स्वाधीनता दिवस कहना अधिक तर्कसंगत होगा। स्वतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलाकर बना है (1) स्व; एवं (2) तंत्र। अर्थात स्वयं का तंत्र, इसलिए स्वतंत्रता दिवस कहना तो तभी न्यायोचित होगा जब स्वयं का तंत्र स्थापित हो। भारत के नागरिकों में आज ''स्व'' के भाव के प्रति जागृति तो दिखाई देने लगी है और वे ''भारत के हित सर्वोपरि हैं'' की चर्चा करने लगे हैं। परंतु, भारत में तंत्र अभी भी मां भारती के प्रति समर्पित भाव से कार्य करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे कभी कभी असामाजिक तत्व अपने भारत विरोधी एजेंडा पर कार्य करते हुए दिखाई दे जाते हैं और भारत के विभिन्न समाजों में अशांति फैलाने में सफल हो जाते हैं। स्व के तंत्र के स्थापित होने से आश्य यह है कि देश में हिंदू सनातन संस्कृति का अनुपालन सुनिश्चित हो।

प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु था। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों सहित लगभग समस्त क्षेत्रों में भारतीय सनातन संस्कृति का दबदबा था। भारत को उस खंडकाल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से पूरे विश्व से विद्यार्थी भारत में आते थे। भारत पर शक, हूण, कुषाण एवं यवन के आक्रमण हुए, परंतु भारत पर उनके कुछ समय के शासन के पश्चात वे भारतीय सनातन संस्कृति में ही रच बस गए एवं भारत का हिस्सा बन गए। परंतु, अरब के देशों से मुसलमान एवं ब्रिटेन से अंग्रेजों के भारत पर चले शासन के दौरान उन्होंने भारतीय नागरिकों का बलात धर्म परिवर्तन करवाया, स्थानीय नागरिकों पर अकल्पनीय अत्याचार किए। भारत के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों, मंदिरों एवं ज्ञान के स्थानों को नष्ट किया। अंग्रेजों ने तो भारतीय नागरिकों के साथ छल कपट ~~करते हुए यह भ्रम फैलाया कि अंग्रेजों~~ ने ही भारतीय नागरिकों को जीना सिखाया है अन्यथा भारतीय समाज तो असभ्य, अनपढ़ गंवार था। उन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति पर गहरी चोट की। वे भारतीयों में हीन भावना भरने में सफल रहे। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को नष्ट किया। गुरुकुल नष्ट किए। अंग्रेजों को नौकर चाहिए थे अतः तात्कालिक शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए। इसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली देश में आज भी चल रही है, जिसके अंतर्गत शिक्षित भारतीय केवल नौकरी करने के लिए ही उतावाले नजर आते हैं। वे अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के प्रति रुचि ही प्रकट नहीं करते हैं। भारत में उद्योगपति अपने परिवार की विरासत से ही निकले हैं।

भारत को आक्रांताओं एवं अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से समय समय पर भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों ने युद्ध भी लड़े एवं अपने स्तर पर उस खंडकाल में सफलता भी अर्जित की। जैसे, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणा सांगा आदि के नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार, अंगेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले वीर क्रांतिकारियों में रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के नाम सहज रूप से लिए जा सकते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर मशाल आगे लेकर चलने वाले कई योद्धाओं में महात्मा गांधी, सरदार पटेल एवं सुभाषचंद्र बोस भी शामिल रहे हैं। इसी समय में विवेकानंद एवं डॉक्टर हेडगेवार ने भी सांस्कृतिक चिंतक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन सफलतापूर्वक किया था। इस प्रकार, अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति मिली एवं भारतीय नागरिकों को स्वाधीनता प्राप्त हुई। भारत के लिए यह एक नई सुबह तो थी परंतु यह साथ में विभाजन की त्रासदी भी लेकर आई थी। पूर्व एवं पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में एक नए देश ने भी जन्म लिया और इस दौरान करोड़ों नागरिकों ने अपनी जान गवाईं थी।

आखिर भारत का विभाजन हुआ क्यों? यदि इस विषय पर विचार किया जाय तो ध्यान में आता है कि दरअसल अंग्रेजों ने यह भ्रम फैलाया कि भारत में आर्य बाहर से आए हैं और इस प्रकार वे भारतीय नागरिकों में मतभेद पैदा करने में सफल हुए। साथ ही, उन्हें भारतीय नागरिकों में यह भाव पैदा करने में भी सफलता मिली कि भारत एक भौगोलिक इकाई है एवं यह कई राज्यों को मिलाकर एक देश बना है जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई होती है न कि भौगोलिक इकाई। उस खंडकाल विशेष में अंग्रेजों द्वारा भारत में किया गया मुस्लिम तुष्टिकरण भी भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रवादी मुसलमानों की उपेक्षा की गई थी एवं उस समय की जनभावना को बिलकुल ही नकार दिया गया था, इसके उदाहरण के रूप में 'वन्दे मातरम' कहने पर अंकुश लगाना एवं राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भगवा ध्वज को स्वीकार नहीं करना, का वर्णन किया जा सकता है। और फिर, उस समय विशेष पर भारत का नेतृत्व भी मजबूत हाथों में नहीं था। उक्त कई कारणों के चलते भारत को विभाजन की विभीषिका को झेलना पड़ा था और करोड़ों नागरिक इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे।

वैसे तो भारत को पूर्व में भी खंडित किया जाता रहा है परंतु वर्ष 1947 में हुआ विभाजन सबसे अधिक वीभत्स रहा है। वर्ष 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ था, वर्ष 1914 में तिब्बत को भारत से अलग कर दिया गया था, वर्ष 1906 में भूटान एवं वर्ष 1904 में नेपाल को भारत से अलग कर दो नए देश बना दिये गए थे एवं वर्ष 1876 में अफगानिस्तान ने नए देश के रूप में जन्म लिया था। यह सभी विभाजन भारत को पावन भूमि को विखंडित करते हुए सम्पन्न हुए थे। यह सिलसिला वर्ष 1947 में स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भी रुका नहीं एवं वर्ष 1948 में भारत के भूभाग को विखंडित कर श्रीलंका के रूप में नए देश का जन्म हुआ। वर्ष 1948 में ही पाकिस्तान के कुछ कबीलों ने भारत के कश्मीर क्षेत्र पर आक्रमण कर कश्मीर के एक हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे आज 'पाक आकुपाईड कश्मीर' कहा जाता है। वर्ष 1962 में आक्साई चिन भी भारत से विखंडित हो गया था।

उक्त विखंडित हुए भूभाग से भारत का नाता आज भी बना हुआ है। जैसे, अफगानिस्तान में बामियान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित रही हैं, जिन्हें बाद के खंडकाल में तालिबान ने खंडित कर दिया है। महाभारत काल में गांधारी आज के अफगानिस्तान राज्य की निवासी रही है। अफगानिस्तान शिव उपासना का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसी प्रकार पाकिस्तान में तो तक्षशिला विश्वविद्यालय रहा है, जिसमें विश्व के अन्य देशों से विद्यार्थी अधय्यन के लिए आते थे। हिंगलाज माता का मंदिर है, भगवान झूलेलाल का अवतरण इस धरा पर हुआ था, साधु बेला, संत कंवरराम, ऋषि पिंगल, ऋषि पाणिनि भी इसी धरा पर रहे हैं। भगत सिंह, लाला लाजपत राय एवं आचार्य कृपलानी जैसे देशभक्तों ने भी इसी धरा पर जन्म लिया था। बंगला देश में भी आज ढाकेश्वरी मंदिर स्थित है जिसके नाम पर ही बांग्लादेश की राजधानी को ढाका कहा जाता है। जगदीश चंद्र बोस एवं विपिन चंद्र पाल जैसे महान देशभक्तों ने भी इसी धरा पर जन्म लिया है। नेपाल तो अभी हाल ही के समय तक हिंदू राष्ट्र ही रहा है एवं यहां पर कैलाश मानसरोवर, पशुपति नाथ मंदिर, जनकपुर जहां माता सीता का जन्म हुआ था एवं विश्व प्रसिद्ध लुम्बिनी, आदि नेपाल में ही स्थित हैं। इस दृष्टि से यह ध्यान में आता है कि भारत को एक बार पुनः अखंड क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि भारत से अलग हुए इन सभी देशों की सांस्कृतिक विरासत तो एक ही दिखाई देती हैं।

महर्षि अरविंद तो कहते ही थे कि भारत अखंड होगा क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा है। स्वामी विवेकानंद जी को भरोसा था कि भारत एक सनातन राष्ट्र के रूप में अखंड होगा ही। आज हम सभी भारतवासियों को यह विश्वास अपने मन में जगाना होगा कि भारत एक अखंड राष्ट्र होगा ही इसके लिए मेहनत की पराकाष्ठा जरूर करनी होगी। हिंदू एक संस्कृति है न कि पूजा पद्धति, इस प्रकार का व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। अखंड भारत में समस्त मत पंथों को मानने वाले नागरिकों को अपनी पूजा पद्धति के लिए छूट होगी ही। इस संदर्भ में विघटनकारी सोच की राजनैतिक पराजय अति आवश्यक है। भविष्य में केवल भारत ही अखंड होगा, ऐसा भी नहीं है। इसके पूर्व एवं पश्चिमी जर्मनी एक हो चुके हैं, वियतमान में भी इसी संदर्भ में बाहरी षडयंत्र विफल हो चुके हैं। इजराईल देश भी तो अनवरत साधना से ही बन पाया है, फिर भारत क्यों नहीं अखंड हो सकता।(लेखक- प्रहलाद सबनानी / ईएमएस)

मामूली बारिश में शहर जलमग्न होना, व्यवस्था की नाकामी

वर्षा ऋतु का सावन माह अपने शबाब पर है। देश के विभिन्न भागों में हलकी,तेज़ तो कहीं बहुत तेज़ बारिश के समाचार हैं। पिछले दिनों 10 -11 अगस्त को पंजाब,हिमाचल व हरियाणा के कई इलाक़ों में तेज़ बारिश हुई। इसी बारिश का प्रकोप हरियाणा के भी कई ज़िलों में देखने को मिला।परन्तु अम्बाला शहर में 11 अगस्त रविवार की सुबह और दोपहर में केवल दो दो घंटे की बारिश ने तो लगभग पूरे शहर को ही डुबो कर रख दिया। न तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई व इतनी देर तक चली न कहीं से बाढ़ का पानी आया। परन्तु पूरा शहर पानी पानी हो गया। शहर का दृश्य ऐसा था गोया सड़कें नदी दिखाई दे रही थीं । हज़ारों घरों व दुकानों में पानी भरा हुआ था। अनेक बाज़ार बंद थे । अनेक वाहन सड़कों पर पानी में फंसे हुए थे। लोगों का कारोबार चौपट था। हद तो यह है कि रेलवे लाइन पर भी पानी भरा था और उसे पंप द्वारा निकालने की कोशिश की जा रही थी। बारिश के मौसम में अम्बाला शहर के एक बड़े इलाक़े को अक्सर ही इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

परन्तु सवाल यह है कि ऐसा क्यों और शहरवासियों की यह दुर्दशा कब तक? और यह भी कि क्या इसके लिये सरकार व सम्बंधित व्यवस्था की कोई ज़िम्मेदारी भी है ? अम्बाला शहर में पिछले दस वर्षों से एक ही भाजपा विधायक निर्वाचित हो रहे हैं। इन्हें मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में वर्ष 2022-23 में 14 वीं हरियाणा विधानसभा में हरियाणा के प्रथम सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया था। यह विधायक प्रदेश के सभी 90 विधायकों में इसलिये भी प्रथम पाए गये थे क्योंकि वे सदन में जनहित के मुद्दे उठाते थे। शायद इसी योग्यता के चलते ही इन्हें वर्तमान नायब सिंह सरकार में मंत्री का पद भी मिल गया है । कुछ वर्ष पूर्व जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं को प्रधान सेवक कहलाने लगे थे उस समय इन विधायक जी ने भी अपने नाम में विधायक के स्थान पर नगर सेवक लिखवाना शुरू कर दिया था।

लिहाज़ा आज जब मात्र दो घंटे की बारिश में शहर में जल प्रलय हो जाता है तो लोगों का यह पूछना स्वभाविक है कि जिस विधानसभा क्षेत्र के जनहित के मुद्दे आप सदन में उठाते थे जिसके चलते आपको हरियाणा का प्रथम सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया था वे मुद्दे आख़िर क्या थे ? उन मुद्दों में प्रत्येक वर्ष बारिश में शहर में जल प्रलय हो जाने जैसा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भी था अथवा नहीं ? यदि था तो आपके दस वर्षों के शासन काल में इसमें क्या प्रगति हुई ? पार्क, तालाब आदि जो बन रहे थे वे भी आधे अधूरे हैं। पूरे शहर जाम हैं व अभी से टूटने भी लगे हैं। इसी बारिश के पहले विधायक जी की टीम ने एक वीडियो वायरल की जिसमें दिखाई दिया कि मंत्री जी स्वयं नाले की सफ़ाई का निरीक्षण कर रहे हैं और सफ़ाई कर्मियों को सख़्त निर्देश दे रहे हैं। उस वीडिओ को देखकर ऐसा लगा कि शायद इस बार विधायक जी के मंत्री बन जाने के बाद नगर वासियों को बरसाती जलप्रलय रुपी नर्क से मुक्ति मिल जाएगी। परन्तु इस बार तो केवल दो घंटे में ही पूरा शहर पानी पानी हो गया ?

विधायक जी के हाथों से उद्घाटन किया हुआ सिटी रेल स्टेशन के साथ लगता सबसे व्यस्त रेल अंडरपास भी है। इसे विधायक जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर पिछले साल ही उद्घाटित किया था। यह रेल अंडरपास बरसात में स्वीमिंग पूल बना रहता है। यहीं नहीं बल्कि बारिश में शहर के तीनों अंडर पास तालाब बन जाते हैं। गोया न ही अंडर पास के पानी की व्यवस्थित निकासी है न ही शहर के मुख्य नालों व नालियों की। परन्तु आपको विकास कार्य पूरे वर्ष होते दिखाई देगा। विकास कैसा ? कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक, तो कहीं एल ई डी की चमकदार रौशनी ,कहीं कुछ चौक पर लगी लाल बत्तियां तो कहीं चौक चौराहों पर स्टील द्वारा की गयी सजावटें। कुछ ही दिनों बाद लाल बत्तियां भी बंद और एल ई डी भी गुल। निर्माणाधीन पार्कों में लगी पत्थरों की क़ीमती जालियां अभी से टूटने लगी हैं। परन्तु इनसबसे जनता को क्या दिलचस्पी। अम्बाला शहर की जनता की सबसे बड़ी समस्या है शहरी जल भराव। और इससे निजात पाने का एकमात्र उपाय है जल निकासी व इसका सुचारु निष्पादन और इसके लिये कारगर,समुचित व भ्रष्टाचार मुक्त योजना।

आज शहर के अधिकांश नाले न केवल जाम पड़े हैं बल्कि टूटे हुए भी हैं। कई जगह तो टूटे हुये नालों का लेवल साथ लगती कालोनियों की ज़मीन के बराबर है। परिणामस्वरूप नालों में ज़रा भी पानी ओवरफ़्लो होता है वह आगे बढ़ने के बजाये कॉलोनी में घुस आता है। शहर की सीवरेज व्यवस्था लगभग फ़ेल हो चुकी है। जगह जगह सीवर के मेन होल ओवर फ़्लो हैं। ओवर फ़्लो सीवर का गंदा व बदबूदार पानी कालोनियों में फैल रहा है। कई जगह तो सीवर के मेन होल के या तो ढक्कन टूट गए हैं या फिर पूरा मेन होल ही धंस गया है। ज़िला प्रशासन सहित इस व्यवस्था से सम्बंधित अधिकारियों को स्थानीय समाजसेवियों व पत्रकारों द्वारा कई बार इस दुर्व्यवस्था व बारिश में होने वाले संभावित जलप्रलय के प्रति सचेत भी किया गया। परन्तु नतीजा वही है जो लगभग हर साल बारिश में दिखाई देता है। इसी दुर्व्यवस्था के चलते हरियाणा की सबसे बड़ी कपड़ा मार्किट प्रभावित होती है। तमाम दुकानों में पानी भरने से करोड़ों का नुक़्सान हो जाता है। दुकानें बंद,ग्राहकों का आवागमन बंद,सड़कें नदी बन जाती हैं। हद तो यह है कि ज़िलाधिकारी कार्यालय के चारों ओर कई कई दिन तक पानी भरा रहता है ,स्टेट बैंक की शहर की सबसे मुख्य ब्रांच में पानी घुसा रहता है ,नगर निगम के चौक जगाधरी गेट पर जलभराव ,धनाढयों व नव धनाढयों के रहने वाले कथित पॉश इलाक़े सेक्टर्स व मॉडल टाउन,इनको चौक,जंडली, प्रेम नगर, आदि सभी जगह पानी रुका रहता है। शुकुल कुंड रोड,बादशाही बाग़ ,सोनिया कॉलोनी,रणजीत नगर,महावीर नगर जैसे दर्जनों इलाक़े जलमग्न रहते हैं। लोगों के घरों के फ़र्नीचर और अनेक ज़रूरी सामान बरसाती पानी घुसने से ख़राब हो जाते हैं। लोगों का काम काज ठप्प हो जाता है। शहर में जब तक पानी की निकासी न हो तब तक दुर्गन्ध का साम्राज्य रहता है। मामूली सी बारिश में शहर का जलमग्न हो जाना निःसंदेह केवल संबद्ध व्यवस्था की नाकामी का ही परिणाम है जो जनता भुगतने के लिये मजबूर रहती है। जनता को हर साल बारिश में होने वाली ऐसी परेशानियों के लिये किसी न किसी को ज़िम्मेदार तो ठहरना ही पड़ेगा ? (लेखिका- निर्मल रानी/ईएमएस)

जम्मू-कश्मीर में चुनावःफिर अग्निपरीक्षा

नयी सरकार ने पहला अच्छा काम किया है कि दस साल बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का साहस जुटाया। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के चुनाव तो होंगे लेकिन शायद ये राज्य भी दिल्ली की तरह केंद्र शासित राज्य बना रहेगा यानि एक और भीगी बिल्ली। जम्मू-कश्मीर के साथ हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव की घोषणा की गयी है लेकिन महाराष्ट्र और झारखण्ड ,बिहार के विधानसभा चुनावों की घोषणा को रोक दिया गया है। इनके बारे में घोषणा सरकार की सुविधानुसार की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के चुनाव एक दशक पहले हुए थे । पांच साल से इस खंडित राज्य में केंद्र का शासन है ,यानि एक लाट साहब सूबे की जनता को सम्हाले हुए हैं। इन पांच सालों में केंद्र की सरकार ने विधानसभा चुनाव क्षेत्रों का मन-माफिक परिसीमन भी कर लिया है। लाट साहब के अधिकार भी अनाप-शनाप बढ़ा दिए हैं ,लेकिन न सूबे में शांति आयी और न समृद्धि। जम्मू-कश्मीर आज भी हमारे सैनिकों और नागरिकों की बलि ले रहा है और केंद्र सरकार संत बनी बैठी है। बावजूद सरकार ने यहां विधानसभा चुनाव कराने का साहस जुटाया है इसलिए उसे बधाई दी जाना चाहिए ,अन्यथा यहां के लोगों के लिए तो चुनाव एक दिवा-स्वप्न हो चुका था।

दरअसल जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के चुनाव हमारे देश की बैशाखियों पर टिकी सरकार का भविष्य तय करने वाले होंगे। इन चुनावों के जरिये राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा,ये भी तय हो जाएगा। चार महीने बाद 4 तारीख को ही एक बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पता नहीं कैसे 4 तारीख को फिर से चुनाव परिणामों के लिए मुकर्रर किया है जबकि ये तारीख माननीय मोदी जी और उनकी भाजपा के लिए मनहूस साबित हुई है। ड याद कीजिये 4 जून की तारीख .जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में चुनाव होंगे, जबकि हरियाणा की 90 सीटों पर एक चरण में ही चुनाव होंगे. दोनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे. लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी और कांग्रेस चुनावी अखाड़े में एक बार फिर आमने- सामने होंगे. लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला सीधा मुकाबला है।

ऐसा माना जा रहा था कि निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर और हरियाणा समेत चार राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख़ें अभी घोषित नहीं की गईं। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव की घोषणाओं के बाद ही विपक्षी दलों ने राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया है। केंद्र की सरकार जम्मू-कश्मीर को दोबारा से पूर्ण राज्य बनाने के मुद्दे पर मौन साधकर बैठी हुई है। स्वाभाविक भी है। केंद्र के पास अभी इतना साहस नहीं है कि वो जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे सके। हालाँकि यदि सरकार ऐसा करती तो उसे वाह-वाही मिल सकती थी ,लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि केंद्र जम्मू-कश्मीर को दिल्ली की तरह भीगी बिल्ली बनाकर रखना चाहता है ,ताकि यहां से धारा 370 उठाने के उसके फैसले को न्यायोचित ठहराया जा सके।

केंद्र ने महाराष्ट्र और बिहार चुनाव टालकर अपनी कमजोरी जाहिर कर दी है । इस फैसले से केंचुआ की हैसियत पर भी सवाल उठेंगे की जो केंचुआ पूरे देश में चुनाव करने में सक्षम है क्या वो चार राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा सकता। लेकिन हमारे यहां एक कहावत है कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी ? एक न एक दिन तो उसे हकीकत का सामना करना ही पडेगा। सवाल ये भी है कि क्या केंचुआ सरकार के इशारों पर कथक कर रहा है ? क्या उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं बची कि वो एक साथ चार राज्यों के विधानसभा चुनाव करा सके ?

आपको याद होगा कि केंचुआ ने जम्मू-कश्मीर राज्य में विधानसभा सीटों को लेकर नए सिरे से परिसीमन भी कराया था। लिहाजा राज्य में विधानसभा की सीटें बढ़कर 90 हो गई हैं। राज्य के पुनर्गठन से पहले यहां विधानसभा की कुल 87 सीटें थीं, लेकिन लद्दाख-कारगिल के अलग होने से यहां विधानसभा की कुल 83 सीटें ही रह गई थीं। परिसीमन में यहां विधानसभा की सात नई सीटें बनी थीं।राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 74 सीटें सामान्य हैं, जबकि एसटी के लिए नौ और एसटी के लिए सात सीटें आरक्षित हैं। यही नहीं, अब राज्य में विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा जो पहले छह वर्ष का होता था। आपको ये भी याद रखना चाहिए की दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा ने हाल में हुए लोकसभा चुनावों में घाटी में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, ऐसे में यह देखना भी रोचक होगा कि विधानसभा में भाजपा क्या रणनीति अपनाती है।ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस चुनाव में 87 वर्षीय डॉ फारुख अब्दुल्ला भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं ,हालाँकि उनकी उम्र हज करने की हो चुकी है।

हरियाणा में पिछले दस वर्षों से भाजपा सत्ता में है। ऐसे में उसके सामने राज्य में सत्ता पर फिर से काबिज होना जहां एक बड़ी चुनौती है । हाल के लोकसभा चुनावों में भाजपा को करारी पराजय का न सिर्फ सामना करना पड़ा अपितु राज्य में नेतृत्व परिवर्तन भी करना पड़ा। वहीं बदले समीकरण में राज्य में कांग्रेस व आप जैसे दल भी मजबूती से मैदान में दिखने की जिद्दोजहद में जुटे हैं। इन दो राज्यों के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और फिर बिहार में विधानसभा के चुनाव कराये जाना हैं। यानि अब देश लगातार चुनावी मोड में रहने वाला है। अब देश की जनता को आने वाले कुछ महीनों तक विकास की बात भूल जाना चाहिये । अब हर दिन उसे टीवी चैनलों पर कहीं न कहीं माननीय नेताओं के सजीव भाषण सुनने को मिलेंगे। नयी गारंटियां मिलेंगीं। नए जुमले मिलेंगे। लेकिन जो होगा सो होगा,उसे टाला नहीं जा सकता। अब नारी शक्ति वंदन और वक्फ बोर्ड की बात भूल जाइये। याद रखिये सिर्फ और सिर्फ चुनाव। हम चुनाव प्रधान देश में रहते जो हैं। (लेखक-राकेश अचल/ईएमएस)

शब्द पहेली - 8101

बाएँ से दाएँ

1. रमण योग्य-4
4. साल,वर्ष-3
6. बांया-2
7. राय,वोट-2
9. तकरार,कहासुनी-4
11. अंधकार,अंधेरा-3
12. सरल,आसान-3
13. चील,ईगल-2
14. देवदास की प्रेमिका-2
15. सूली,क्रूस-3
17. कारण-3
19. मन को हरने वाला-4
21. कार्य,काज-2
23. बाण,तीर-2
24. दबाना,कुचलना-3
25. हाथी चलाने वाला-4

ऊपर से नीचे

1. परंपरा,रीति-रिवाज-4
2. संस्कृत में 'मेरा'-2
3. भरोसा,विश्वास-3
4. दीदी,भगिनी-3
5. समान,एक जैसा-2
8. अंधेरा,अंधकार-3
9. बोरिया बिस्तर-4
10. रिहा-2
12. तालाब,जलाशय-4
15. तमीज,शिष्टता-3
16. मछली,एक राशि-2
18. ज्वरताप-4
19. चिंतन,विचार-3
20. रनिवास (उर्दू-3)
22. नशा,अभिमान-2
23. पार्थिव देह,लाश-2

शब्द पहेली -8100 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

फाइनल में अपने शीर्ष स्तर पर नहीं पहुंच पाया : नीरज

नई दिल्ली (ईएमएस)। पेरिस ओलंपिक में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से सभी को स्वर्ण की उम्मीद थी पर वह रजत पदक ही जीत पाये। इसी को लेकर अब नीरज ने माना है कि वह फाइनल में अपने शीर्ष स्तर तक नहीं पहुंच पाये थे। नीरज ने पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जीता था पर इस बार वह इस बार पेरिस में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत ही जीत पाए। नीरज ने कहा कि वह फाइनल में मानसिक रूप से तैयार थे पर शारीरिक रुप में कमी रह गयी थी। इसी कारण फाइनल के दौरान उनका लेगवर्क वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। साथ ही कहा अगर आपकी दौड़ इतनी अच्छी नहीं है, तो आप बहुत दूर तक थ्रो नहीं कर सकते।

नीरज ने कहा कि मेरा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना होना चाहिये। इसके अलावा पिछले दो से तीन साल से मेरी फिटनेस भी उनकी इतनी अच्छी नहीं रही थी। मेरी तकनीक और रनवे उतना अच्छा नहीं था। मैं केवल एक ही सही थ्रो करने में सफल रहा, बाकी फाउल हुए। नीरज कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नंबर एक पर नहीं पहुंच सकता। वहीं पेरिस के स्वर्ण विजेता अरशद नदीम का पिछला सर्वश्रेष्ठ 90.18 मीटर था जो उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में फेंका था और मेरा पिछला सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.94 मीटर था। मैं इस बार अपनी अंतिम सीमा तक नहीं पहुंचा। इसका कारण रनवे पर मेरा लेगवर्क उम्मीद के अनुरुप नहीं होना रहा। अरशद के थ्रो के तुरंत बाद मेरा थ्रो अच्छा था क्योंकि मैं बेहद सकारात्मक था। नीरज ने कहा कि अब वह 22 अगस्त से शुरू हो रही लॉज़ेन डायमंड लीग में भाग लेंगे।

2024 महिला टी20 विश्वकप की मेजबानी करना चाहता है जिम्बाब्वे

हरारे (ईएमएस)। बांग्लादेश में जारी हिंसा और खराब हालातों को देखते हुए जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वह महिला टी-20 विश्वकप की मेजबानी करने तैयार है। इससे पहले बांग्लादेश बोर्ड (बीसीबी) ने भारतीय बोर्ड (बीसीसीआई) से विश्वकप की मेजबानी करने की अपील की थी पर बीसीसीआई ने इंकार कर दिया था। ऐसे में जिम्बाब्वे बोर्ड को मेजबानी मिलने का अवसर दिखा और उसने प्रस्ताव दे दिया। जिम्बाब्वे ने अब तक विश्वकप क्वालीफायर 2023 और 2018 की मेजबानी की थी। उसकी टीम हालांकि क्वालीफाइ नहीं होने कारण एक बार भी विश्वकप में भाग नहीं ले पाई है। जिम्बाब्वे अन्य बड़े आयोजनों की तैयारी के लिए भी टूर्नामेंट का मेजबान बनना चाहता है।

जिम्बाब्वे साल 2026 में नामीबिया के साथ पुरुष अंडर 19 विश्वकप और 2027 में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के साथ मिलकर एकदिवसीय विश्वकप की सह मेजबानी भी करेगा। तब तक देश में दो और नये अंतरराष्ट्रीय मैदान भ बन जाएंगे। जिम्बाब्वे बोर्ड हरारे स्पोर्ट्स क्लब और बुलावायो में क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के मैदान को टी-20 विश्वकप के आयोजन के तौर पर पेश कर सकता है। इन मैदानों पर 2023 विश्वकप क्वालीफायर के सभी मैच हुए थे।

जिम्बाब्वे को मेजबानी मिलने की इसलिए भी उम्मीद है क्योंकि उसके यहां अक्टूबर में गर्मियों का मौसम रहेगा और बारिश की बाधा नहीं होगी। जिम्बाब्वे के अलावा संयुक्त अरब अमीरत (यूएई) भी मेजबानी की दौड़ में शामिल है। अब ये देखना है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) किसको मेजबानी का अवसर देती है

भाग्यश्री और सुमित पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत के ध्वजवाहक होंगे

नई दिल्ली (ईएमएस)। भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत के ध्वजवाहक होंगे। पैरालंपिक खेल 28 अगस्त से शुरु होंगे। इस बार के पैरालंपिक खेलों में भारत अपना सबसे बड़ा 84 सदस्यीय दल भेज रहा है। इससे पहले टोक्यों पैरालंपिक खेलों में 54 एथलीटों ने भाग लिया था।

भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) ने कहा कि इस बार भारत तीन नई स्पर्धाओं पैरा साईकलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में भी भाग लेगा। इन तीनों खेलों को मिलाकर भारतीय खिलाड़ी पैरालंपिक में कुल 12 खेलों में उतरेंगे। गोला फेंक खिलाड़ी भाग्यश्री ने 2022 एशियाई पैरा खेलों में एफ34 स्पर्धा में रजत पदक जीता था और वह टोक्यो पैरालंपिक खेलों में सातवें स्थान पर रही थीं। उन्होंने विश्व कप और विश्व पैरा एथलेटिक्स खेलों में भी पदक जीते थे। वहीं पैरा भाला फेंक एथलीट सुमित ने साल 2020 टोक्यो पैरालंपिक में 68.55 मीटर के विश्व रिकॉर्ड थ्रो के साथ ही स्वर्ण पदक हासिल किया था। इसके अलावा उन्होंने 2023 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता तथा 2022 एशियाई खेल में 73.29 मीटर के थ्रो के साथ ही एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था।

सिनसिनाटी ओपन में हारे अल्कराज ने रैकेट जमीन पर पटका

सिनसिनाटी (ईएमएस)। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में गेल मोनफिल्स ने हरा दिया। मोनफिल्स के हाथों तीन सेट तक चले इस कड़े मुकाबले में 4-6, 7-6 (7-5), 6-4 से हारने के बाद अल्कराज भड़क गये और उन्होंने अपना रैकेट जमीन पर मारकर तोड़ दिया।

दूसरी वरीयता प्राप्त अल्कराज ने इस मैच को अपने करियर का अब तक का सबसे खराब मैच करार दिया। इस खिलाड़ी ने कहा कि मैंने वास्तव में बहुत अच्छी तैयारी कर रही थी और मैं अच्छा महसूस कर रहा था पर मैं उस तरह का खेल नहीं दिखा पाया जैसी की उम्मीद थी। मैं इस मैच को भूल कर आगे बढ़ना चाहता हूं। अब मेरा लक्ष्य और अमेरिकी ओपन में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं। अमेरिकी ओपन इसी माह 26 अगस्त से शुरू होगा।

पेरिस ओलंपिक में छाये रहे ये विवाद

नई दिल्ली (ईएमएस)। हाल में समाप्त हुए पेरिस ओलंपिक में इस बार कई विवाद भी छाये रहे। इन खेलों में संयुक्त राज्य अमेरिका 126 पदकों (40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य) के साथ सबसे सफल देश रहा। वहीं चीन इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा। इस बार के ओलंपिक खेलों में कई प्रकार के विवाद भी उठे।

अल्जीरियाई बॉक्सर इमान खलीफा के जेंडर का मामला सभी प्रतियोगी मुक्केबाजों ने उठाया। खलीफा ने चीन की यांग लियू को हराकर अल्जीरिया के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। जीत से ज्यादा इमान खलीफा जेंडर को लेकर विवादों में रही। खलीफा पर बायलॉजिकली पुरुष मेल होने का आरोप लगा था। यह भी दावा किया गया कि उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर पुरुषों की तरह ही है। खलीफा इससे पहले 2023 विश्व चैम्पियनशिप में जेंडर एलिजिबिलिटी में अयोग्या पाये जाने के बाद बाहर कर दी गयीं थीं। खलीफा ने राउंड-16 में इटली की बॉक्सर एंजेला कारिनी के खिलाफ सिर्फ 46 सेकंड में ही मैच जीतत लिया था। जंजेला ने बाद में खलीफा के जेंडर पर सवाल उठाये और कहा कि कि इस प्रकार का प्रकार उसने पहले नहीं देखा था। वहीं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने अड़ियल रवैये का परिचय देते हुए खलीफा पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया।

इन खेलों में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल से ठीक पहले वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश ने महिलाओं की 50 किलो फ्रीस्टाइल के फाइनल में जगह बनाई थी पर केवल 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया। इस मामले में विनेश की संयुक्त रुप से रजत दिये जाने की अपील भी खेल पंचाट ने ठुकरा दी।

विनेश ने अपने को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ खेल पंचाट में अपील की थी जिसे खारिज कर दिया गया।

अमेरिका की जिम्नास्ट जॉर्डन चाइल्स से कांस्य पदक छीन लिया गया। वहीं फ्लोर इवेंट में रोमानिया की एना बारबोसु को हारने के बाद भी कांस्य पदक मिल गया। इवेंट में जॉर्डन तीसरे और एना चौथे नंबर पर रही थीं। मैच में हार के बाद एना बारबोसु और उनकी टीम ने खेल पंचाट में अपील कर कहा था कि जॉर्डन चाइल्स को गलत तरीके से अंक दिए गए हैं, जिस वजह से वो तीसरे नंबर पर रही थीं।

इस मामले में खेल पंचाट ने एना को सही पाया और जॉर्डन चाइल्स का स्कोर घटाकर 13.666 कर दिया गया।. इसके साथ ही वो पांचवें नंबर पर पहुंच गईं. जबकि एना बारबोसु तीसरे नंबर पर आ गईं।

ऑस्ट्रेलिया हॉकी खिलाड़ी टॉम क्रेग पेरिस ओलंपिक के दौरान कोकीन खरीदने के विवाद में उलझ गए। ऑस्ट्रेलियाई पुरुष हॉकी टीम के सदस्य क्रेग को कोकीन खरीदने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें 17 वर्षीय संदिग्ध विक्रेता के साथ हिरासत में लिया गया पर क्रेग को बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और कोई औपचारिक आरोप दर्ज नहीं किया गया।अपनी रिहाई के बाद टॉम क्रेग ने पूरे वाकये के लिए माफी मांगी. क्रेग ने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं।

1अक्टूबर से लागू होंगे शेयर बायबैक के नए नियम

नई दिल्ली (ईएमएस)। शेयर बॉयबैक पर नया टैक्स सिस्टम लागू होने वाला है। नए नियम (एँपि 1 अक्टूबर से लागू होंगे। नए नियम के तहत अगर कोई निवेशक को शेयर बॉयबैक से फायदा मिलता है तो उसे डिविडेंड माना जाएगा। अब डिविडेंड के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। शेयर बायबैक में जितनी राशि शेयरधारक को मिलेगी उसी हिसाब से पूंजीगत लाभ या हानि की गणना की जाएगी। इस साल जुलाई में पेश हुए यूनियन बजट में वित्त मंत्री ने शेयरों की बॉयबैक से हुई इनकम पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव पेश किया था। इसके तहत शेयर की पुनर्खरीद से होने वाली आय को लाभांश के रूप में माना जाएगा। इस नए टैक्स सिस्टम के तहत शेयर बायबैक को कंपनी का अतिरिक्त आमदनी आ जाएगा और उस पर टैक्स लगाया जाएगा। इन नए नियमों को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इससे निवेशकों का बोझ बढ़ सकता है और शेयर बायबैक में भी कमी आ सकती है।

शेयर बायबैक के नए नियम से निवेशकों को फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। बाजार के जानकारों ने कहा ?कि नए नियमों के तहत कंपनियों को बायबैक की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और नियमों का पालन करना होगा। इससे निवेशकों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें अधिक स्पष्टता मिलेगी कि कंपनियां किस तरह से बायबैक कर रही हैं और इसका उनके निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन नियमों के कारण कंपनियों को बायबैक की प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है। इससे शेयर की कीमतों पर त्वरित लाभ की संभावना कम हो सकती है, जो उन निवेशकों के लिए नुकसानदेह हो सकता है जो जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसके अलावा, कंपनियों पर अनुपालन की अतिरिक्त लागत भी आ सकती है, जो उनके मुनाफे को प्रभावित कर सकती है।

आरबीआई ने पी2पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए सख्त किए मानदंड

मुंबई (ईएमएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी -पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी2पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म) के लिए मानदंड सख्त कर दिए। आरबीआई द्वारा जारी संशोधित मास्टर निर्देश के अनुसार पी2पी प्लेटफॉर्म को निवेश उत्पाद के रूप में पीयर-टू-पीयर लेंडिंग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जिसमें अवधि-लिंक्ड सुनिश्चित न्यूनतम रिटर्न, लिक्विडिटी विकल्प आदि जैसी विशेषताएं हों। बैंक ने कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म को किसी भी बीमा उत्पाद को क्रॉस-सेल नहीं करना चाहिए, जो क्रेडिट वृद्धि या क्रेडिट गारंटी की प्रकृति का हो।

अब निजी कंपनियां एक बार में 100 से ज्यादा नहीं खरीद सकेंगी सिम कार्ड

सरकार ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने बनाए नए नियम

नई दिल्ली,(ईएमएस)। सिम कार्ड के नए नियमों के तहत अब प्राइवेट कंपनियां एक बार में 100 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद सकेंगी। इसके लिए उन्हें अगली बार फिर से अप्लाई करना होगा। सिम कार्ड जारी करने से पहले यूजर का ई-वेरीफिकेशन करना जरूरी होगा, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके।

सिम कार्ड के नियमों में बदलाव हो सकता है। कुछ समय पहले ही सिम कार्ड को लेकर नया नियम आया था। नए नियमों का सबसे ज्यादा असर यूजर्स पर पड़ने वाला है। क्योंकि सरकार की तरफ से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए सिम कार्ड से संबंधित नए नियम बनाए गए हैं।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए कहा कि अब निजी कंपनियां 100 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद सकेंगी। एक समय में 100 सिम कार्ड ही खरीद पाएंगी। ऑनलाइन स्कैम और सिम कार्ड की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। अगर किसी भी कंपनी को इससे ज्यादा सिम चाहिए तो उन्हें रिक्वेस्ट करनी होंगी। ये रिक्वेस्ट कंपनियों के एमडी द्वारा की जाएगी।

कंपनी को बल्क में सिम कार्ड चाहिए तो उन्हें 100 सिम कार्ड के बैच में ही इसे अप्लाई करना होगा। इसके बाद ज्यादा सिम हासिल करने के लिए उन्हें अगले दिन दोबारा अप्लाई करना होगा। इसमें एमडी के साथ यूजर का भी ई-वेरीफिकेशन होगा। फोटोग्राफ के साथ पूरी जांच करने के बाद ही सिम कार्ड इशू किया जाएगा। कंपनियों पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी। वह अनलिमिटेड नंबर ऑफ सिम खरीद सकती थीं। लेकिन अब इसमें भी बदलाव करने के बाद जरूरी हो गया है कि कर्मचारी खुद सिम का ई-वेरीफिकेशन करेगा। उसे पूरा करने के बाद ही सिम कार्ड इस्तेमाल करने लायक होगी।

सिक कार्ड एक्टिवेशन का प्रोसेस पूरा तभी होगा जब यूजर की केवॉयसी पूरी तरह अपडेट होगी। इससे पहले ऐसा नहीं किया जाएगा यानी सरकार की तरफ से इस पर पूरी तरह काबू पाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार बहुत सारे फैसले ले रही है जो सीधा यूजर्स को प्रभावित करने वाले हैं।

वर्ष 2027 तक भारत बन जाएगा ?विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्थाः गीता गोपीनाथ

नई ?दिल्ली (ईएमएस)। भारत सरकार ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का नारा दिया है। इस कड़ी में सबसे पहले सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। अब सरकार के इस लक्ष्य को आईएमएफ ने भी संभव बताया है। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के लिि आईएमएफ ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है।

दरअसल, इंटरनेशनल मोनेटरी फंड की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ का कहना है कि भारत साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मालूम हो कि मौजूदा समय में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। गोपीनाथ ने कहा ?कि पिछले वित्त वर्ष में हमने जैसी उम्मीद जताई थी, भारत की अर्थव्यवस्था उससे बेहतर कर रही है। गीता गोपीनाथ ने ग्रोथ रेट में अपग्रेड के पीछे कई तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा कि टू-व्हीलर्स सेल्स और एफएमसीजी सेक्टर फिर से वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इस साल मानसून भी अच्छा करता दिख रहा है, जिससे एग्रीकल्चर इनकम में बढ़ोतरी की संभावना है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम, 2019 में संशोधन

नई दिल्ली (ईएमएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के आम बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी निवेश के लिए नियमों और विनियमों को सरल बनाने की घोषणा की थी। इसी घोषणा के अनुसरण में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने जारी अधिसूचना के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) नियम, 2019 में संशोधन किया है। इन संशोधनों का उद्देश्य सीमा पार शेयर स्वैप को सरल बनाना तथा विदेशी कंपनी इक्विटी उपकरणों के बदले भारतीय कंपनी इक्विटी उपकरणों को जारी करने या स्थानांतरित करने का प्रावधान करना है। इससे विलय, अधिग्रहण तथा अन्य रणनीतिक पहलों के माध्यम से भारतीय कंपनियों के वैश्विक विस्तार में सुविधा होगी। इससे भारतीय कंपनियां नए बाजारों तक पहुंच सकेंगी तथा दुनिया भर में अपनी उपस्थिति बढ़ा सकेंगी।

गूगल भारत सहित छह देशों में लाएगा 'एआई ओवरव्यू' फीचर

नई दिल्ली (ईएमएस)। टेक सेक्टर की प्रमुख कंपनी गूगल ने भारत सहित छह देशों में 'एआई ओवरव्यू' फीचर लाने की घोषणा कर दी है। भारत में कंपनी अंग्रेजी और हिंदी में 'एआई ओवरव्यू' शुरू कर रही है और साथ ही देश में पहली बार लोकप्रिय फीचर्स भी पेश कर रही है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा ?कि यह आपको लैंग्वेज टॉगल बटन के साथ अंग्रेजी और हिंदी रिज्ल्ट के बीच आसानी से स्विच करने में मदद करेगा, और सुनो बटन पर टैप करके टेक्स्ट-टू-स्पीच के साथ प्रतिक्रियाओं को सुनने में मदद करेगा। इसे भारत, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इंडोनेशिया, मैक्सिको और ब्राजील में शुरू किया जा रहा है। सर्च के प्रोडक्ट मैनेजमेंट की एक वरिष्ठ निदेशक ने कहा कि टेस्टिंग के दौरान हमने देखा कि भारतीय यूजर्स अन्य देशों की तुलना में एआई ओवरव्यू के जवाबों को अधिक बार सुनते हैं। हम सर्च करते समय प्रासंगिक वेबसाइटों की जांच करने के लिए और अधिक तरीके पेश कर रहे हैं। डेस्कटॉप पर एआई ओवरव्यू के लिए दाहिने हाथ के लिंक डिस्प्ले के साथ ऊपरी दाईं ओर साइट आइकन पर टैप करके मोबाइल पर भी पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे हम एआई को विकसित करते हैं, हम विभिन्न स्रोतों से लोगों को जानकारी तक पहुंचने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कंपनी एआई ओवरव्यू के टेक्स्ट के भीतर सीधे प्रासंगिक वेब पेजों के लिंक जोड़ने का भी परीक्षण कर रही है। इससे लोगों के लिए क्लिक करना और उन साइटों पर जाना और भी आसान हो जाता है, जिनमें उनकी रुचि है।

पूंजीगत खर्च में पीछे रहीं निफ्टी-50 सूचकांक में शामिल कंपनियां

मुंबई (ईएमएस)। निफ्टी 50 सूचकांक में शामिल देश की प्रमुख कंपनियों का पूंजीगत खर्च मार्च में समाप्त वित्त वर्ष में 5.89 लाख करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2023 में इन कंपनियों के 7.43 लाख करोड़ रुपये के कुल पूंजीगत खर्च से यह 20.7 फीसदी कम रहा। स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा कंपनियों की सालाना रिपोर्ट से ये आंकड़े प्राप्त हुए हैं। सकल संपत्ति निर्माण और पूंजीगत कार्यों की प्रगति में गिरावट का मुख्य कारण देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूंजीगत खर्च घटना है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) की सालाना रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में 1.39 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च किया, जो वित्त वर्ष 2023 के 2.45 लाख करोड़ रुपये से कम है। आरआईएल को छोड़कर निफ्टी-50 की बाकी कंपनियों का सकल संपत्ति निर्माण लगभग सपाट रहा है। पूंजीगत खर्च में कटौती के बावजूद आरआईएल वित्त वर्ष 2024 में सकल संपत्ति निर्माण में सबसे आगे रही है और उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल उत्पादक कंपनी ओएनजीसी है। ओएनजीसी ने वित्त वर्ष 2024 में 68,418 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च किया था। इसी तरह आदित्य बिड़ला समूह की होल्डिंग कंपनी ग्रासिम ने 46,612 करोड़ रुपये और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी ने 43,614 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया।

क्रेडिट कार्ड बंद करने में देरी करने पर बैंक को देना होगा जुर्माना

मुंबई (ईएमएस)। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अगर कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड को बंद कराने का आवेदन देता है तो उस पर 7 दिन के अंदर प्रॉसेस शुरू करना जरूरी होता है। अगर कार्ड जारी करने वाली बैंक या संस्था ऐसा नहीं कर पाती है तो 7 दिन की अवधि के बाद उस पर 500 रुपये हर दिन के हिसाब से जुर्माना लगता है और यह रा?शि ग्राहक को देनी होती है। हालांकि एक बात का ध्यान देना जरूरी है कि आपके क्रेडिट कार्ड का कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए। यह नियम आरबीआई ने साल 2022 में पेश किया था। किसी भी क्रेडिट कार्ड को बंद कराने से पहले आपको उसका बकाया चुकाना होता है। जब तक बकाया नहीं चुकाया जाता है तब तक क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होगा। बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड बंद करवाने से पहले रिवॉर्ड प्वाइंट रिडीम नहीं करते हैं। आपने खर्च करके ये प्वाइंट कमाया है। ऐसे में यह रिडीम करना आपका हक ह। कई बार लोग अपने क्रेडिट कार्ड पर कुछ रिकरिंग पेमेंट्स की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, ओटीटी मंथली चार्ज या कुछ और. बंद कराने से पहले इसे पूरी तरह से क्लियर कर दें। अब आपको बैंक को फोन करके बताना होगा कि आप क्रेडिट कार्ड बंद करना चाहते हैं। इसके बाद वह डिटेल मांगेगा, जिसके बाद प्रॉसेस शुरू किया जाएगा।

स्वीडन अपने ही नागरिकों को देश छोड़ने के पैसे देगा - बड़ों को 80 हजार, बच्चों को 40 हजार मिलेंगे

स्टॉकहोम(ईएमएस)। स्वीडन ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया है। स्वीडन की इमीग्रेशन मिनिस्टर मारिया माल्मर स्टेनगार्ड ने ये प्रस्ताव पेश किया है। स्टेनगार्ड ने कहा कि जिन्हें स्वीडन की संस्कृति पसंद नहीं है या फिर वे लोग जो यहां घुलमिल नहीं पाए हैं वे स्वीडन छोड़ सकते हैं। स्वीडन में अभी भी देश छोड़ने पर पैसे दिए जाते हैं। पहले विदेश से आकर स्वीडन में बसने वाले नागरिकों पर ही ये नियम लागू होता था, लेकिन नए प्रावधान के तहत जन्मजात नागरिकों पर भी ये नियम लागू होगा।

मौजूदा नियमों के मुताबिक यदि कोई स्वीडिश नागरिक देश छोड़ता है तो उसे 10 हजार स्वीडिश क्रोन (80 हजार रुपए) मिलते हैं। बच्चों को देश छोड़ने पर 40 हजार रुपए मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें किराए के पैसे भी मिलते हैं। ये पैसा उन्हें एक बार में ही देश छोड़ने से पहले मिल जाता है।

50 सालों में पहली बार देश छोड़ने वाले लोग बढ़े

नए प्रस्ताव के मुताबिक, अब इसमें देश के सभी नागरिकों को शामिल किया जाएगा। देश छोड़कर जाने वालों को और अधिक पैसे देने और इसे बढ़ाकर 14,800 डॉलर (करीब 12 लाख रुपए) करने पर विचार हुआ था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। सरकार का कहना है कि अगर देश छोड़ने पर पैसे बढ़ाए गए तो इससे संदेश जाएगा कि स्वीडन लोगों को पसंद नहीं करता। हैरानी की बात ये है कि स्वीडन में ये प्रस्ताव तब पास हुआ है जब देश छोड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक 2024 में स्वीडन में आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। 50 सालों में ये पहली बार हुआ है।

प्रवासियों की आबादी बढ़ी, मूल आबादी देश छोड़ रही

स्वीडन में भले ही देश छोड़ने वाले लोग बढ़े हों मगर यहां की आबादी बढ़ती जा रही है। दरअसर स्वीडन के मूल वासी अमेरिका जैसे देशों में ठिकाना तलाश रहे हैं। वहीं, प्रवासियों के लिए स्वीडन पसंदीदा जगह बना हुआ है। स्वीडन में प्रवासियों की संख्या 20 लाख से भी ज्यादा हो गई है, जो स्वीडन की कुल आबादी का पांचवां हिस्सा है। पहले विदेश से आकर स्वीडन में बसने वाले नागरिकों पर ही ये नियम लागू होता था, लेकिन नए प्रावधान के तहत जन्मजात नागरिकों पर भी ये नियम लागू होगा। प्रवासियों की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई पाबंदियां लगा चुकी हैं। स्वीडन में सीरिया, सोमालिया, ईरान और इराक से आए लोगों की आबादी काफी ज्यादा है।

हमास ने संघर्ष विराम के प्रस्ताव को खारिज किया.....बाइडेन की कटूनीति पर फिरा पानी

गाजा (ईएमएस)। हमास ने कहा कि गाजा में संघर्ष विराम के प्रस्ताव में नई शर्तों को खारिज कर दिया है, जिसे कतर में दो दिनों की वार्ता के दौरान अमेरिकी नेतृत्व वाले मध्यस्थों ने पेश किया था। 10 माह से जारी युद्ध में झेली गई पीड़ा को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास अब तक विफल रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वार्ता के नवीनतम दौर पर कहा कि हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। विदेश विभाग ने कहा कि वह नवीनतम प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए सप्ताहांत अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को इजरायल भेज रहे हैं।

मिस्र, कतर और अमेरिकी मध्यस्थ मई में बाइडेन द्वारा शुरू में रेखांकित किए गए ढांचे के विवरण को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे उन्होंने कहा कि इजरायल ने प्रस्तावित किया था। एक संयुक्त बयान में, मध्यस्थों ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो शेष अंतराल को पाटता है और आने वाले दिनों में मानवीय प्रावधानों और बंधक-कैदियों की अदला-बदली पर बारीकियों को सुलझाने के लिए काम करना जारी रखेगा। एक त्वरित सौदे को सुरक्षित करने के उद्देश्य से वार्ता अगले सप्ताह के अंत से पहले काहिरा में फिर से शुरू होने वाली है। हमास, जो दोहा वार्ता में शामिल नहीं हुआ था, ने नवीनतम योजना में इजरायल की ओर से नई शर्तों के विरोध की घोषणा की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मध्यस्थों से हमास पर बाइडेन के ढांचे को स्वीकार करने के लिए दबाव डालने का आह्वान किया।

ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा इजरायल पर हमला करने की धमकियों ने गाजा युद्धविराम को समाप्त करने के प्रयासों में नई तत्परता ला दी है, मध्यस्थ व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने की उम्मीद में एक समझौते की मांग कर रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चेतावनी दी, क्षेत्र में किसी को भी इस प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

रुस और भारत वैश्विक मंच पर गहन सहयोग की तलाश रहे संभावनाएं

मास्को,(ईएमएस)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार एंटोन कोब्याकोव ने रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने के तौर-तरीकों पर बातचीत हुई।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोब्याकोव को एक टीवी चैनल पर यह कहते सुना गया है कि भारत और रूस व्यापार, ऊर्जा, विज्ञान, निवेश, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण में समान स्तर पर सहयोग करते हैं। खास बात यह है कि समेकन संधि के ढांचे के भीतर परस्पर सहयोग को भी मजबूत किया जा रहा है। इसका संप्रभु बहुध्रुवीय विश्व के गठन के लिए खास महत्व है। रिपोर्ट में कोब्याकोव और कुमार के बीच वार्ता का विषय द्विपक्षीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाना था। दोनों नेताओं ने कज़ान में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और मॉस्को में ब्रिक्स व्यापार मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी पर भी बातचीत की। ये अक्टूबर 2024 में होना है।

दुनिया की सबसे कम उम्र की पीएम बनी थाइलैंड की पैटोंगटार्न शिनावात्रा

बैंकॉक (ईएमएस)। थाइलैंड की संसद ने शुक्रवार को पैटोंगटार्न शिनावात्रा को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। पैटोंगटार्न थाइलैंड के पूर्व पीएम थाकसिन शिनावात्रा की सबसे छोटी बेटी हैं। वह शिनावात्रा परिवार से थाईलैंड की कमाल संभालने वाली तीसरी नेता बनी हैं। इसके पहले उनके पिता और उनकी चाची यिंगलुक शिनावात्रा यह पद संभाल चुके हैं। थाकसिन शिनावात्रा को तख्तापलट के जरिए सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। 38 साल में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही वह इस पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की नेता बन गई हैं। पैटोंगटार्न अपनी चाची के बाद थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं।

पैंटोंगटार्न थाईलैंड की सत्तारूढ़ पार्टी फेउ थाई की नेता हैं। वह निर्वाचित सांसद नहीं हैं। पीएम पद का उम्मीदवार होने के लिए उनका सांसद होना जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री पद के लिए पैटोंगटार्न एकमात्र उम्मीदवार थीं। संसद में उनके पक्ष में 310 वोट पड़े, जबकि 145 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया। 27 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।

इसके पहले थाईलैंड की संवैधानिक कोर्ट ने पीएम श्रेथा थाविसिन को कैबिनेट सदस्य की नियुक्ति में नैतिकता का पालन न करने पर पद से हटा दिया था। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में जेल जा चुके पूर्व वकील को नियुक्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि श्रेथा ने नैतिक मानकों को पूरा नहीं करने वाले शख्स को मंत्री नियुक्त करके संविधान का उल्लंघन किया है। श्रेथा को एक साल से भी कम समय में प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था।

पाकिस्तान को लेकर योगी ने ऐसा क्या कहा......पूरे देश में मचगई हलचल

इस्लामाबाद (ईएमएस)। भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने पाकिस्तान ने हलचल मचा दी है। योगी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर कहा था कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए इतिहास से समाप्त होगा। योगी ने महर्षि अरविंद के साल 1947 में दिए गए बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। योगी के बयान पर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने प्रतिक्रिया दी है।

बासित ने पाकिस्तान के खत्म होने की भविष्यवाणी का विरोध कर कहा कि उनका देश बना रहेगा। हालांकि, बासित को योगी के बयान का मतलब ही समझ नहीं आया और ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की।

बासित ने इस्लाम को पाकिस्तान का सबसे बड़ा आधार बताया। बासित ने कहा कि योगी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में अस्तित्व नहीं है। बल्कि, हमारे देश का आधार ही इस्लाम है। यह आध्यात्मिक ही है। मुझे नहीं समझ पाता कि महर्षि अरविंद ने विचार कहां से लिया और अब विचार को योगी ने दोहराया है। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने योगी आदित्यनाथ के बयान को अफसोसजनक बताया था।

14 अगस्त को संबोधन में योगी ने पाकिस्तान के खात्मे की भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि जब आध्यात्मिक जगत में किसी का वास्तविक स्वरूप नहीं है, पाकिस्तान को नष्ट ही होना है। उसकी नश्वरता पर हमें शक नहीं करना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि यह होगा।

अब यूपीएससी पास किए बिना बन सकेंगे नौकरशाह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और अंतरराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वालों के लिए आईएएस बनने की राह खुली

नई दिल्ली(ईएमएस)। अब संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा पास किए बिना भी नौकरशाह बना जा सकता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और अंतरराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वालों के लिए आईएएस बनने की राह खोलते हुए यूपीएससी ने बिना परीक्षा पास किए विभिन्न मंत्रालयों में बतौर संयुक्त सचिव, निदेशक व उपसचिव नियुक्त करने का विज्ञापन जारी कर दिया है।

यूपीएससी ने 45 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इस तरह से होने वाली नियुक्त के लिए जारी अधिसूचना को लैटरल एंट्री नोटिफिकेशन नाम दिया गया है। खास बात है कि लैटरल एंट्री के जरिए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और अंतरराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वालों के लिए आईएएस बनने की राह खोल दी गई है। वे भी लैटरल एंट्री के जरिए फटाफट आईएएस बनकर किसी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर सकेंगे।

लैटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में योग्य उम्मीदवारों की सीधी भर्ती होगी। हालांकि, इस प्रक्रिया के द्वारा पहले भी उम्मीदवार चयनित किए गए हैं। यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों पर लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती के जरिए नियुक्ति की जाएगी।

नौकरी तीन वर्ष के अनुबंध पर

आवेदकों को यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं करनी पड़ेगी। यह नौकरी तीन वर्ष के अनुबंध पर रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में 17 सितंबर तक संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयनित आवेदकों को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के मुख्यालय में तैनात किया जाएगा। संयुक्त सचिव स्तर के पद के लिए 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। निदेशक के पद के लिए 10 और उप सचिव के पदों के लिए सात साल की नौकरी का अनुभव होना अनिवार्य है।

यूपीएससी ने बिना परीक्षा पास किए विभिन्न मंत्रालयों में बतौर संयुक्त सचिव, निदेशक व उपसचिव नियुक्त करने का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारी इस भर्ती के लिए योग्य नहीं होंगे। यानी वे आवेदन नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो उक्त पदों के समकक्ष पदों पर काम कर रहे हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय, वैधानिक निकाय, यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त शोध संस्थान, निजी कंपनी, अंतरराष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोग लैटरल एंट्री वाले पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त सचिव पद के लिए आयु सीमा 40 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, इन्हें पे लेवल 14 में रखा जाएगा। यानी इन्हें डीए मिलाकर 2,70,000 रुपये का मासिक वेतन मिलेगा। नियमानुसार, यात्रा भत्ता और मकान का किराया भी दिया जाएगा। वहीं, निदेशक पद के लिए आयु सीमा 35 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन्हें पे लेवल 13 में शामिल किया जाएगा। यानी डीए को मिलाकर 2,32,000 रुपये वेतन मिलेगा। डिप्टी सेक्रेटरी के लिए आयु सीमा 32 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी पे लेवल 12 में रहेंगे। इन्हें डीए मिलाकर 1,52,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।

यूपीएससी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के 10 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इनमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यावरण पॉलिसी और पर्यावरण कानून, डिजिटल इकोनॉमी, फिन टेक और साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी एंड प्लान, एनडीएमए, शिपिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक/कमर्शियल/ इंडस्ट्रियल और रिन्यूएबल एनर्जी।

डायरेक्टर-डिप्टी सेक्रेटरी के पदों पर सीधी भर्ती

डायरेक्टर-डिप्टी सेक्रेटरी के 33 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इनमें क्लाइमेट चेंज- सॉयल कन्जरवेशन, क्रेडिट, फॉरेस्टरी, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, नैचुरल फार्मिंग, नैचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट/ रेनिफाइड फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वॉटर मैनेजमेंट, एविएशन मैनेजमेंट, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, कमोडिटी प्राइसिंग, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, एडु लॉ, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, अंतरराष्ट्रीय कानून, इकोनॉमिस्ट, टैक्स पॉलिसी, मेनुफेक्चरिंग आटो, मेनुफेक्चरिंग-आटो सेक्टर एसीसी बैटरीज, टेक्निकल, अर्बन वॉटर मैनेजमेंट, डिजिटल मीडिया, समन्वय एवं प्रबंधन, टेक्निकल, वॉटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वॉश सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून, सर्विस लॉ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज, सूचना तकनीक, इकोनॉमिक/ कमर्शियल/ इंडस्ट्रियल आदि।

टीचर ने किया 6 बच्चियों का रेप, 28 साल जेल की सजा

ताइपे(ईएमएस)। ताइवान में एक टीचर को 6 बच्चियों का रेप करने के मामले में 28 साल जेल की सजा सुनाई गई है। ताइपे टाइम्स के मुताबिक 30 साल के किंडरगार्टन टीचर माओ चुन शेन पर छह लड़कियों से रेप के 11 मामलों, शोषण के 207 मामलों और अश्लील तस्वीरें-वीडियो बनाने के 6 मामलों में दोषी ठहराया गया था। ताइपे के कोर्ट ने कहा कि माओ को कुल 224 मामलों में दोषी पाया गया है, जिसमें कानून के हिसाब से उसकी कुल सजा 1252 साल और 6 महीने होगी। हालांकि, उसे 28 साल की सजा सुनाई गई। माओ अभी इसके खिलाफ अपील कर सकता है।

कारोबारी व्यापार शुरु करने शहबाज सरकार पर बना रहे दबाव, भारत नहीं दे रहा भाव

इस्लामाबाद,(ईएमएस)। पाकिस्तान को भारत भाव नहीं दे रहा है जिससे शहबाज सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के साथ कोई भी द्विपक्षीय बातचीत नहीं हो रही है। फिर चाहे यह पर्दे के पीछे से हो या आमने सामने से। भारत के साथ व्यापार को फिर से बहाल करने पर भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। इससे पहले नवाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तक भारत से फिर से बातचीत शुरू करने के लिए कहा जा चुका है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत में मोदी के तीसरी बात पीएम बनने के बाद बातचीत शुरू होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

पाकिस्तान के कई कारोबारी कह चुके हैं कि भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू किया जाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने धारा 370 का मुद्दा उठाया और मांग की कि भारत इसे बहाल करे। उन्होंने कहा कि भारत के धारा 370 खत्म करने के बाद ही उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को बंद किया है। उन्होंने कहा कि यह हालात अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। बलोच ने कहा कि इस समय भारत के साथ व्यापार को फिर से बहाल करने को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है।

वहीं भारत ने कहा है कि जब तक कश्मीर में आतंकवादियों को पाकिस्तान भेजना बंद नहीं करता है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच फरवरी 2021 में सीजफायर समझौता हुआ था जो अभी तक है। पाकिस्तानी की ओर से भेज आतंकियों ने इन दिनों जम्मू और कश्मीर में काफी हमले किए हैं। इन हमलों में कई जवान शहीद हो गए हैं।

बलोच ने भारतीय सेना की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और दुनियाभर के देशों से मांग की कि वे कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को अपना समर्थन देना जारी रखेगा। इससे पहले नवाज शरीफ ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए शांति की बात कही थी। वहीं आतंकियों के हमले के बीच भारत ने कड़ा जवाब देना जरुरी समझा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पिछले दिनों इशारों में भारत को धमकी दी थी।

चीन में 4000 शवों को चोरी कर बेचा गया, 80 लोग गिरफ्तार

बीजिंग (ईएमएस)। चीन में 2015 से लेकर 2023 के बीच में 4000 से अधिक मानव शवों को चोरी छुपे बेचा गया। इस कारोबार में लगभग 400 करोड रुपए शव चोरों ने कमाए। पुलिस ने 80 लोगों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है।

चोरों का यह गिरोह बोन ग्राफ्ट के लिए शवों की चोरी कर उन्हें बेचता था। चीन के कई राज्यों के शव दाह गृह और मेडिकल लैबोरेट्री से शवों की चोरी की जाती थी। सोशल मीडिया में जब शव के चोरी की खबरें सामने आई। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की थी।

25 साल में पहली बार गाजा में मिला पोलियो का संक्रमण, युद्ध विराम की मांग

गाजा,(ईएमएस)। गाजा में हमास और इजराइल युद्ध के बीच सालों बाद गाजा में पोलियो का पहला मामला सामने आया है। दीर अल-बलाह शहर में दस माह के एक बच्चे में इसके संक्रमण की पुष्टि हुई है। फलस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे में पोलियो के लक्षण दिखाई देने के बाद जांच की गई, जिसमें संक्रमण पाया गया। इस बच्चे को पोलियो रोधी टीके की एक भी खुराक नहीं पिलाई गई थी। यह संक्रमण आमतौर पर पांच साल के कम उम्र के बच्चों में पाया जाता है और यह दूषित जल आदि से फैलता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे देश हैं, जहां पोलियो का संक्रमण आज तक नहीं थमा। डब्ल्यूएचओ ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी (यूनिसेफ) ने इजराइल और हमास से सात दिन के लिए युद्ध विराम की मांग की है, ताकि 6,40,000 फलस्तीनी बच्चों को पोलियो से बचाव का टीका लगाया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि पिछले महीने गाजा के दो प्रमुख शहरों के अपशिष्ट जल में पोलियो का वायरस मिला था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक क्षेत्र पिछले 25 सालों से पोलियो मुक्त है।

बांग्लादेश में शरिया कानून लागू होगा, हिंदू अपने धर्म का पालन करेंगे,इस्लामिक संगठन के नेता ने रखे अपने विचार

ढाका,(ईएमएस)। बांग्लादेश का सबसे बड़े इस्लामिक संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम 2010 में बना था। ये संगठन जल्द ही धर्म की प्रेशर पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के विरोध से लेकर अल्पसंख्यकों पर हमले में भी इसका नाम आया। शेख हसीना सेकुलर होने की वजह से उनका विरोधी रहा यह संगठन नदेश में शरिया कानून लागू करने की वकालत करता रहा है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में संगठन से जुड़े अबुल फैयाज मोहम्मद खालिद हुसैन धार्मिक मामलों के सलाहकार हैं। संगठन के वाइस प्रेसिडेंट मुहिउद्दीन रब्बानी भारत में देवबंद से पढ़े हैं। संगठन के निशाने पर सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी रहते हैं। एक साक्षात्कार में मुहिउद्दीन रब्बानी ने कहा कि हम अहमदियाओं को मुस्लिम नहीं मानते। वे काफिर हैं। हमारा संगठन बांग्लादेश में इस्लाम, कुरआन, हदीस की हिफाजत के लिए काम करता है। हम इस्लाम की हिफाजत करने और दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुसलमानों के लिए काम करते हैं। हमारा संगठन इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है।

उन्होंने कि ये देश अंग्रेजों से आजाद हुआ, तब मुसलमानों का दावा था कि हम इस्लामी निजाम पर इस मुल्क को चलाएंगे। हम ये अब भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम ऐसा निजाम है, जिसमें गैर मुस्लिम के अधिकार की भी बात होती है। इस्लाम के अलावा दूसरे किसी धर्म में ऐसी बात नहीं है। प्रतिमाओं के संबंध में वो कहते हैं कि मंदिरों और मूर्तियों को कैसे तोड़ देंगे। हिंदू अपने धर्म का पालन करेगा, उनकी मूर्ति की हिफाजत की जाएगी।

इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए तो इस्लाम खुद ही सबको इंसाफ के तौर पर हक देगा। जहां तक म्यूजिक की बात है, तो जो इस्लाम में जायज होगा, हम उसके आधार पर तय करेंगे। हम म्यूजिक, आर्ट पसंद नहीं करते। इसके खिलाफ पुरजोर बात करेंगे। उन्होंने भारत के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि आप हमारे पड़ोसी हैं। हमारे भाई हैं। आप सभी हिंदुओं के साथ मिल-जुलकर रहें, जैसा हम बांग्लादेश में रहते हैं।

कोलकाता रेप-मर्डर के विरोध में अहमदाबाद समेत कई जिलों में डॉक्टरों ने रैली निकाली

वडोदरा17 अगस्त

कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या का मामला और गंभीर हो गया है. इस घटना को लेकर देशभर के चिकित्सा समुदाय में आक्रोश है। फिर इस घटना का असर गुजरात पर भी पड़ा है. मृत डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार के अस्पतालों के डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। फिर आज (17 अगस्त) डॉक्टरों ने अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और जामनगर में रैली निकाली.

अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल कैंपस के बीजे मेडिकल, जीसीएस हॉस्पिटल समेत सभी कॉलेजों के छात्रों ने विरोध दर्ज कराया है. पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जीसीएस हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर ने रैली निकाली है. आज (17 अगस्त) सूरत नवी सिविल और पालिका के स्मीथर अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों और इंटर्न डॉक्टरों ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले में पीड़िता के लिए न्याय और आरोपियों को कड़ी सजा की मांग को लेकर रैली निकाली। डॉक्टरों द्वारा काले कपड़े पहनकर और नारे लिखी तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. इसके अलावा रैली निकालकर कलेक्टर को शिकायती पत्र दिया गया है।

राजकोट समेत सौराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है. निजी अस्पताल के डॉक्टर भी ओपीडी बंद रखकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं. डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर जिला कलक्टर को आवेदन दिया जाएगा। आईबीजांचमें शामिल हुई जामनगर के सभी निजी अस्पताल हड़ताल पर हैं पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डयूटी पर मौजूद रेजिडेंट डॉक्टर के साथ अनबन की गूंज पूरे देश में सुनाई दी और इसका असर जामनगर तक हुआ। वीडियोः कोलकाता रेप-मर्डर 4 के खिलाफ अहमदाबाद समेत कई जिलों में डॉक्टरों की रैली-

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है। राष्ट्रीय स्तर पर आई.एम.ए. आई.एम.ए. द्वारा लिए गए निर्णय के बाद जामनगर से संबद्ध सभी डॉक्टर और उन डॉक्टरों से संबद्ध कॉर्पोरेट, निजी और ट्रस्ट अस्पताल 24 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे। आज (17 अगस्त) सुबह 6 बजे से 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक यानी 24 घंटे के लिए सभी अस्पतालों में सभी गैर-आपातकालीन सेवाएं बंद रहेंगी. कोलकाता की घटना के विरोध में गुजरात समेत देशभर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं. गुजरात आयुर्वेद एसोसिएशन ने भी हड़ताल का समर्थन किया है. गुजरात के 25 हजार से ज्यादा आयुर्वेद डॉक्टरों ने बंद का ऐलान किया है. मांग की गई है कि इस घटना में पीड़िता को न्याय दिया जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए.

श्रावणी पूनम पर डाकोर मंदिर में दर्शन का समय में परिवर्तन

डाकोर ,17 अगस्त

रणछोड़रायजी महाराज डाकोर मंदिर का समय : श्रावण सुदी पूर्णिमा के दिन यात्राधाम डाकोर में रणछोड़रायजी के दर्शन का कार्यक्रम जहां घोषित कर दिया गया है, वहीं उचित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रणछोड़रायजी के दर्शन के लिए किए गए परिवर्तन का निर्णय ट्रस्ट द्वारा लिया गया है। भक्त. जिसमें 19 अगस्त, रक्षाबंधन के दिन, श्रावण सुद पूनम, सोमवार सुबह 4:45 बजे मंगला आरती की जाएगी। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस व्यवस्था की भी तैयारी शुरू कर दी गयी है.

डाकोर में रणछोड़रायजी के दर्शन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जिसमें श्रावण सुद पूनम सोमवार 19 अगस्त को सुबह 4:45 बजे मंगला आरती की जाएगी। इस बीच रात 8:30 बजे तक दर्शन किए जा सकेंगे. इसके बाद 9:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक दर्शन खुले रहेंगे. जब दोपहर 2:00 बजे महाभोग आरती की जाएगी. जिसमें दोपहर 2:30 बजे तक दर्शन किए जा सकेंगे। इसके बाद शाम 4:00 बजे उत्थापन आरती होगी। जिसमें वैष्णवों के लिए दर्शन खोले जायेंगे और नित्य नियम से सेवा पूजा कर श्री ठाकोरजी का सुविधाजनक पारण होगा.

ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी के दिन श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा. इसके अलावा अगले दिन यानी 27 अगस्त को नंदा महोत्सव मनाया जाएगा.

रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर वडोदरा नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की जांचः 69 नमूने लिए गए

वडोदरा,17 अगस्त

श्रावण के पवित्र महीने और रक्षा बंधन के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए, नगर पालिका ने आटा, तैयार भोजन, मिठाइयाँ, फरसाण और कच्चे माल आदि बेचने वाले निर्माताओं, मिठाई-फरसाण की दुकानों आदि में निरीक्षण किया।

खाद्य शाखा के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शहर के विभिन्न इलाकों में आटा, रेडी टू ईट फूड, मिठाई, फरसाण एवं कच्चा माल निर्माताओं, मिठाई-फरसाण दुकानों आदि की जांच की। 69 के बीच नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

श्रावण एवं रक्षाबंधन के पवित्र माह को ध्यान में रखते हुए शहर के जन स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है नगर निगम आयुक्त दिलीप राणा के निर्देशानुसार अभिहित अधिकारी एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुकेश वैद्य ने भोजन की अलग-अलग टीमें बनाईं खाद्य विभाग के सुरक्षा अधिकारियों द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आटा, तैयार भोजन का वितरण किया गया तथा आवारा भोजन, मिठाइयाँ, फरसाण तथा कच्चा माल आदि बेचने वाले निर्माताओं, मिठाई-फरसाण की दुकानों आदि में निरीक्षण अभियान चलाया गया। 5 तारीख से 16 तारीख तक धनिष्ठा चेकिंग की गई. खाद्य निरीक्षण अभियान के दौरान केसरी पेंदा, खोया (लूज़), केसर पेंदा, केसरी मलाई पेंदा, मावा रसबरी मिठाई, चॉकलेट काजू कतरी, केस2 कतरी सिल्वे2 पत्ती के साथ, बादाम केस2 पेंदा, घी, चौलाई का आटा, मोरिया आटा, फलियां आटा, मीक फराली आटा, खोपरा पैटीज़, साबूदाना वड़ा, फराली पत्र, फराली चेवडो, केला वेफर और आलू वेफर आदि के 69 नमूने लिए गए। नमूनों को विश्लेषण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में भेजा गया।

खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा अपनी दुकानों में इस तरह से बोर्ड भी लगाए जाते हैं कि ग्राहक अपनी दुकानों में मिठाई और फरसाण बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों जैसे माओ, बर्फी, घी, बिनौला तेल, पामोलीन तेल, तिल के तेल का उल्लेख कर सकें। सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम एवं विनियम 2011 के अनुसार पदाभिहित अधिकारी एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सघन जांच अभियान एवं सैम्पलिंग प्रक्रिया अपनाई गई है। साथ ही शेडयूल-4 के अनुसार साफ-सफाई रखने का सख्त निर्देश दिया गया.

राज्य सरकार ने वडोदरा में रिंग रोड निर्माण के लिए 316.78 करोड़ रुपये आवंटित किये

वडोदरा, 17 अगस्त

वडोदरा शहर और इसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के लगातार बढ़ते विकास के दायरे को देखते हुए, राज्य सरकार ने रु। स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत 316.78 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.

वुडा ने जीयूडीएम में एक प्रस्तुति और प्रस्ताव दिया, जिसमें वडोदरा महानगर और इसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को कम करने के साथ-साथ सुनियोजित विकास के लिए रिंग रोड की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के सामने रखे जाने के बाद उन्होंने वडोदरा शहरी विकास प्राधिकरण वूडा को रिंग रोड के निर्माण के लिए 316.78 करोड़ रुपये मंजूर कर दिये हैं.

वडोदरा में पूरी रिंग रोड 66 किमी है। लंबा और 75 मीटर की चौड़ाई में बनाया जाना है। इसके पहले चरण में 45 मीटर की चौड़ाई के साथ 27.58 किमी. लंबे रिंग रोड के लिए मुख्यमंत्री ने यह राशि आवंटित की है. 27.58 किमी लंबे इस रिंग रोड के पहले चरण के लिए धनराशि आवंटित होने से अब निर्माण कार्य में तेजी आएगी। इससे पूर्वी क्षेत्र में 10.70 कि.मी. तथा पश्चिमी क्षेत्र में 16.84 कि.मी. कार्य कराया जायेगा.

इतना ही नहीं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी-एकता नगर की ओर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक का बोझ कम हो जाएगा और मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग -8 पर वाहनों का आवागमन भी आसान हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र में बनाई जाने वाली 16.84 किमी लंबी रिंग रोड यातायात की भीड़ को कम करेगी और रिंग रोड के आसपास विकास को नई गति देगी।

लॉ कॉलेजों में एलएलबी प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं, एबीवीपी का प्रदर्शन

वडोदरा17 अगस्त

वडोदरा एम एस यूनिवर्सिटीः एमएस यूनिवर्सिटी के लॉ संकाय सहित राज्य के सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी लॉ कॉलेजों में एलएलबी प्रवेश प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है, और एबीवीपी ने आज कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया।

एबीवीपी ने कहा कि एलएलबी प्रवेश प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए. क्योंकि अब अगस्त का महीना भी खत्म होने को है. साथ ही, गुजरात के अर्ध-सरकारी लॉ कॉलेजों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मानदंडों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए और इन कॉलेजों में प्रति छात्र सरकारी अनुदान भी बढ़ाया जाना चाहिए।

एबीवीपी का कहना था कि लंबे समय से अर्धसरकारी कॉलेजों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इस मामले पर पिछले साल भी एक प्रेजेंटेशन दिया गया था. हालाँकि, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है.

अमेरिका में नौकरी दिलाने के नाम पर तीन लोगों से 1.34 करोड़ वसूलने वाले बदमाश एजेंट की गिरफ्तारी

वड़ोदरा,17 अगस्त

अमेरिका में नौकरी दिलाने के नाम पर झूठे दस्तावेज बनाकर वड़ोदरा की दो महिलाओं और बोरसद तालुक की एक महिला समेत तीन लोगों से 1.34 करोड़ रुपये ठगने वाले एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए आरोपी को अदालत में पेश करने से पहले उसे 11 दिन की रिमांड पर लिया।

वडोदरा शहर के अलकापुरी इलाके में आरसी दत्त रोड पर कुंज बंगले में रहने वाले आरोपी हेमल उर्फ मेहुल महेंद्रभाई पटेल का गोरवा सर्कल साराभाई कैंपस में आईटी पार्क में नोटस नाम से ऑफिस था। अमेरिका में नौकरियों के लिए विज्ञापन दिया गया। तो मांजलपुर इलाके में 7,00,000 रुपये की रकम जब्त की गई. उसमें से उसने 1,50,000 रुपये लौटा दिए और बाकी 5,50,000 रुपये नहीं लौटाए. युवक ने पैसे की मांग की और मुझे धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो जो करना है कर लो और मेरे हाथ पड़ोगे तो जान से हाथ धोने की बारी आएगी। इसके अलावा, आरोपी ने अमेरिका में नौकरी के लिए वर्क वीजा दिलाने के नाम पर बोरसाद तालुका में रहने वाली सविताबेन पटेल परिवार के सदस्यों से 1,25,00,000 रुपये और दूसरे खंभे के पास रहने वाली संध्याबेन वैजापुरकर से 4,34,000 रुपये प्राप्त किए थे। .1,34,84,000 . लेकिन कोई अमेरिकी वीज़ा संसाधित नहीं किया गया। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सयाजीगंज शाखा का फर्जी पे-ऑर्डर देकर फिडयूसियरी से 1,00,000 रुपये की धोखाधड़ी की. मांजलपुर के युवक ने गोरवा थाने में शिकायत दर्ज करायी तो पुलिस ने लूट का अपराध दर्ज कर आरोपी हेमल उर्फ मेहुल महेंद्रभाई की गिरफ्तारी के लिए गोरवा पुलिस की अलग टीम गठित की. उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की पूछताछ के लिए अदालत में पेश किया गया और 11 तारीख को उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

वडोदरा में अजवा रोड इलाके में 10 से ज्यादा अवैध पशु शेड हटाए

वडोदरा ,17 अगस्त

वडोदरा शहर के पूर्वी क्षेत्र में कमला नगर झील के आसपास चरवाहों द्वारा अवैध रूप से बनाई गई लगभग 10 गौशालाओं को नगर पालिका की दबाव शाखा द्वारा साफ कर दिया गया। तभी कुछ चरवाहों की नगर निगम टीम से झड़प हो गई। लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए मामले को संभाल लिया.

अग्नि सुरक्षा को लेकर जिले के 275 निजी प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक की गयी

वलसाड,17 अगस्त

वलसाड जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा दिनांक 17/08/2024को जिले के कक्षा-1 से 8 तक के निजी प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को बच्चों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों में पर्याप्त फायर एनओसी/अग्नि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने हेतु और आग सुरक्षा के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के लिए वेदांत मल्टीपर्पज स्कूल, वलसाड में निजी प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्यों की एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिले के 275 निजी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक उपस्थित थे. वलसाड जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी डीबी वसावा एवं उप जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी डॉ.अर्जुनभाई पटेल ने विस्तृत विवरण दिया. अग्नि सुरक्षा मुद्दे की गंभीरता कोदेखते हुए सभी स्कूलों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा, ऑनलाइन उपस्थिति, यू.डी.आई.एस. पर डेटा प्रविष्टि, स्कूल मेंआवश्यकरिकॉर्डबनाए रखना, स्कूल की भौतिक और स्वास्थ्य सुविधाएं, आरटीई नियमों का उचितअनुपालन, एफआरसी के अनुसार शुल्क संग्रह, स्कूल पाठयक्रम और पाठयपुस्तकों का उपयोग और पूर्वजैसेमहत्वपूर्णमुद्दे-प्राथमिक विद्यालय पंजीकरण मामले पर भी जानकारी दी गई।

वडोदरा के अजवा-वारसिया रोड पर देह व्यापार के खिलाफ मामला दर्ज

वड़ोदरा,17 अगस्त

वड़ोदरा के अजवा वर्सिया रोड पर एक घर में चल रहे वेश्यालय को पुलिस ने पकड़ा है और उसके मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। किशनवाड़ी इलाके में महाकाली सोसायटी के पीछे कबीर चौक इलाके में रहने वाली पारुल उर्फ पायल बालकृष्ण ब्रह्मभट्ट द्वारा पिछले कुछ समय से बाहर से लड़कियों को बुलाकर वेश्यालय चलाने की जानकारी मिलने पर मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने छापेमारी की।

पुलिस ने घर से तीन लड़कियों को बचाया. जब सूत्रधार पारुल उर्फ पायल को हिरासत में लिया गया. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि प्रति ग्राहक 1000 से 1500 रुपये वसूल कर देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था.

वडोदरा 'आप' के कई नेता कांग्रेस में शामिल, शक्तिसिंह गोहिल ने किया स्वागत

अहमदाबाद (ईएमएस)वडोदरा जिला आम आदमी पार्टी (आप) के कई नेता आज कांग्रेस में शामिल हो गएं गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने आप से आए नेताओं में पार्टी में स्वागत कियां गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात में भाजपा के राज में लोग त्रस्त हो चुके हैं युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, किसानों के लिए एनपीके, डीएपी, यूरिया खाद नहीं है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, महंगाई आसमान छू रही है, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला हैं ऐसे में गुजरात के हित में सत्ता परिवर्तन जरूरी हैं आज आप के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने जनहित में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला तब लिया हैं इन्हें पता है कि आज कांग्रेस एक सकारात्मक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही हैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शक्तिसिंह गोहिल द्वारा गुजरातियों की सेवा के लिए कांग्रेस के सेवा यज्ञ में शामिल होने के आह्वान को बहुत अच्छा प्रतिभाव मिला है। लगातार कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं कांग्रेस में शामिल होने वाले नेता और कार्यकर्ताओं को शक्ति सिंह गोहिल ने धन्यवाद दियां मनीष दोशी ने बताया कि वडोदरा जिले के आप नेताओं में हरिसिंह अर्जुनसिंह राज, जयेंद्रसिंह जीतसिंह राणा, महेंद्रसिंह रणधीरसिंह वंसदिया, मुकेश कुमार मूलशंकर भट्ट, श्री भरत सिंह अशोकसिंह चावड़ा आज राजीव गांधी भवन में औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने आप के नेताओं और कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत कियां इस अवसर पर हाथ से हाथ जोड़ो के संयोजक इंद्रनील राजगुरु, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक एवं प्रवक्ता मनीष दोशी, वडोदरा जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भास्कर भट्ट, करजन शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षदसिंह सुजानसिंह गोहिल, करजन तालुकाकांग्रेसकेअध्यक्ष भरत अमीन, करजन तालुका कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उम्मीदवार विधान सभा-2022 के लिए पिंटू पटेल उपस्थित रर्हे

सूरत के न्यू सिविल और स्मीमेर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल अगले दिन भी जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर शामिल हुए हैं

सूरत,17 अगस्त

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना के बाद देशभर में गहरी प्रतिक्रिया हुई है. जिसके चलते सूरत शहर समेत पूरे देश के डॉक्टर महिला डॉक्टर और उसके परिवार को न्याय दिलाने और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि, न्यू सिविल और स्मीमेर अस्पताल के रेजिडेंट्स समेत डॉक्टरों ने आज भी हड़ताल जारी रखी और काले कपड़े पहनकर विरोध जताया. इसके साथ ही आज सुबह आईएमए समेत विभिन्न मेडिकल एसोसिएशन और पैरा मेडिकल स्टाफ समेत संगठनों ने रैली निकाली.

प्राप्त विवरण के अनुसार, कलकत्ता के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के जघन्य अपराध के बाद, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सूरत शाखा आज शनिवार सुबह से एक दिन (24 घंटे) विरोध प्रदर्शन करेगी। 18 तारीख को मेडिकल सेवाएं बंद रहेंगी. हालांकि, आपातकालीन सेवाएं चालू हैं। साथ ही शनिवार सुबह न्यू सिविल अस्पताल के सभागार में आमसभा का आयोजन किया गया. इसके बाद सुबह आईएमए सहित विभिन्न डॉक्टर एसोसिएशन के 500 से अधिक डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ ने एकत्रित होकर नवी सिविल से रैली निकाली और कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा। रैली के माध्यम से डॉक्टरों ने पीड़ित डॉक्टर को न्याय और दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की.

न्यू सिविल और स्मीमेर अस्पताल में रेजीडेंट डॉक्टर सहित डॉक्टरों ने काले कपड़े पहनकर हड़ताल जारी रखी और दोनों अस्पतालों के शिक्षक और डॉक्टर सहित वरिष्ठ डॉक्टर ओपीडी में काम कर रहे हैं ताकि मरीजों को परेशानी न हो. अपने काम से अलग होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अब याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

ट्रिब्यूनल ने सूरत नगर निगम कार्यालय के वक्फ संपत्ति के दावे को खारिज किया

सूरत,17 अगस्त

सूरत वक्फ संपत्ति मामलाः केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा पेश किए गए वक्फ रिसर्च बिल-2024 बिल को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ. इस बीच पक्ष-विपक्ष के बीच चर्चा के बाद बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है. सूरत मनपा कार्यालय के स्थान को लेकर विवाद के बीच जब गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड ने मुगलसराय को मुगलसराय की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया, तो आवेदक ने इसे शाहजहा का उत्तराधिकारी बताते हुए फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पूरे मामले पर जब गुजरात वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने प्रतिक्रिया दी.

वर्ष 1644 में शाहजहा की बेटी जहारा ने सूरत में मुगल सराय भवन का लोकार्पण किया। जब यह संपत्ति देश-विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए दान कर दी गई थी। दूसरी ओर, अब्दुल वदोद जारुल्लाह नामक व्यक्ति ने मुगलसराय इमारत पर फारसी में लिखे वक्फनामे के आधार पर शाहजहा का उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए वक्फ अधिनियम की धारा 36 के तहत संपत्ति पर दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया है।

जबकि पूरे मामले में केस हाई कोर्ट में चल रहा है, अक्टूबर 2021 में एक आवेदन पर हाई कोर्ट ने मामला वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था. जिसमें सूरत निगम को मुगलसराय का प्रशासक मात्र मानने वाले वक्फ बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन द्वारा वक्फनामा के आधार पर संपत्ति वक्फ दर्शायी गयी थी. इसके बाद सूरत मनपा ने अपील की और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को बदल दिया.

इसके बाद याचिकाकर्ता ने दोबारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि वह शाहजहा का वारिस है. हालांकि, इन सबके बीच याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट में दायर अपील फिलहाल लंबित है. तत्कालीन गुजरात वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. मोहसिन लोखंडवाला ने कहा, 'देवभूमि द्वारका में हिंदुओं के एक धार्मिक स्थल बेट द्वारका और शायल बेट पर बोर्ड द्वारा कभी भी किसी भी तरह से दावा नहीं किया गया है। जिसमें खास तौर पर वक्फ बोर्ड के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है.' वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता शमसाद पठान ने कहा, '2013 के सर्वे के बाद वक्फ संपत्ति का वितरण नहीं किया गया. जब गुजरात में वक्फ संपत्ति को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है.'

वलसाड राजकीय जिला पुस्तकालय में 9 से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये

वलसाड,17 अगस्त

राजकीय जिला पुस्तकालय वलसाड द्वारा खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधि विभाग के अंतर्गत पुस्तकालय विभाग दिनांक. 9 से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिसमें दिनांक 9 अगस्त को ठविश्व आदिवासी दिवसठ के उत्सव के रूप में आदिवासी समाज से संबंधित पुस्तकों की प्रदर्शनी। 12 अगस्त को डॉ. एस.आर. रंगनाथन की जयंती ठलाइब्रेरियन दिवसठ समारोह के अवसर पर, एक चित्र प्रतियोगिता और पश्चिम की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता और पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

हर घर तिरंगा अभियान-2024 के अंतर्गत 13 अगस्त को ठहर घर तिरंगाठ, 14 अगस्त को वृक्षारोपण एवं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पुस्तकालय में पढ़कर सरकारी सेवाओं में नौकरी पाने वाले मित्रों का सम्मान किया गया। चूंकि पुस्तकालय के नए भवन को एक वर्ष पूरा हो गया है, इसलिए पूरे कार्यक्रम का आयोजन सरकारी जिला पुस्तकालय वलसाड और पुस्तकालय का उपयोग करने वाले छात्रों द्वारा किया गया था। गरबा खेलकर गुजराती संस्कृति की छटा बिखरी।

मस्जिद अमीना द्वारा संचालित मदरसा अशर फुल मदारिस में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया

वलसाड,17 अगस्त

वलसाड कोसंबा रोड, मुश्ताक नगर में 'मस्जिदे अमीना' द्वारा संचालित 'मदरसा अशरफुल मदारिस' में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जिसमें मदरसे के छात्रों ने देश की आजादी के गीत और भारत को आजाद कराने में शहीद हुए वीरों के बलिदान के बारे में बताया, छात्रों ने महात्मा गांधी, भगत सिंह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिशे देहलवी, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बताया। हाफिज जमीन, शेखुल इस्लाम, साचिद अशफाकउल्लाह खान आदि ने व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को ट्राफियां एवं पुरस्कार वितरित किये गये।

मस्जिद अमीना, मुश्ताक नगर, वलसाड के अध्यक्ष हजरत मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने स्वतंत्रता दिवस पर व्याख्यान दिया और कहा कि ठभारत संघठ के दो त्योहारोंः स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर, पूरे भारत में एकता दिखाई देती है और तिरंगे लहराए जाते हैं। हर घर में देखा जाता है. ऐसी एकता सभी धर्मों के लोगों के बीच सदैव बनी रहनी चाहिए, ताकि देश अधिक से अधिक प्रगति कर सके और महाशक्ति बन सके।

हजरत मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने तिरंगे के बारे में आगे कहा कि तिरंगे में केसरिया रंग त्याग और बलिदान है। साधु-संत भी भगवा रंग के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि वे अपना जीवन संसार का त्याग करके व्यतीत करते हैं। तिरंगे में सफेद रंग सद्भाव, मेल-मिलाप और शांति है और तिरंगे में हरा रंग कृषि, कल्याण और समृद्धि है।

तिरंगे में अशोक चक्र गतिशील और प्रगतिशील है। इसके 24 अरों में से 12 अर सुख के और 12 अर दुःख के लक्षण हैं। हर दुख के बाद सुख आता है और यह क्रिया मानव जीवन में चलती रहती है, इसलिए हर हिंदुस्तानी को सबके सुख-दुख में शामिल होना चाहिए और एक-दूसरे का सहयोग और मदद करनी चाहिए। उक्त कार्यक्रम का आयोजन मौलाना यूनुस साहब, मौलाना इनायतुल्लाह साहब एवं हाफिज जुबैर साहब द्वारा किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में मस्जिद, मदरसा ट्रस्ट के सदस्य, एडवोकेट आसिफभाई मंगेरा साहब, अनवरभाई पठान साहब, तौफीकभाई तिमल्या साहब और मुहसिनभाई शेख साहब उपस्थित थे।

वडोदरा में अधिक ब्याज वसूलने की धमकी देने वाले पांच साहूकारों के खिलाफ शिकायत

वडोदरा,17 अगस्त

मोहम्मद साजिद मोहम्मद हनीफभाई दूध वाला वडोदरा में पानीगेट भद्रा कार्यालय के सामने रॉयल अपार्टमेंट में रहकर एक निर्माण श्रमिककेरूप में काम करता है। खुदरा में श्रम अनुबंध सामग्री के साथ निर्माण कार्य भी करें। उन्होंनेसीटी थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहाहैकिगोली लगने के दौरान उन्हें निर्माण कार्य के लिए पैसे की जरूरत थी, कारोबार में भारी आर्थिक नुकसान हुआ था और मुझे अपने परिचित दोस्त और सूदखोर कारोबारी मोइनुद्दीन जहुरदीन शेख निवासी भंडवाड़ा फतेपुरानी से पैसे की जरूरत है. 1,00,000 रुपये14फीसदी ब्याज लिया गया. इसके एवज में 3.36 लाख का भुगतान किया गया था.

पश्चिम रेलवे

विभिन्न कार्य

मंडल रेल प्रबंधक (डब्ल्यूए), पश्चिम रेलवे, छठी मंजिल, इंजीनियरिंग। विभाग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई–400008, क्रमांक संख्या: 1. ई–निविदा सूचना संख्या- बीसीटी/24–25/136 दिनांक 13.08.2024 आमंत्रित करता है। कार्य और स्थान: विरार जोरावासन अनुभाग: ट्रैक गिट्टी यानी आईएस/आरडीएसओ–जीई/0001:2023) फरवरी–2023 या नवीनतम के लिए विनिर्देश के अनुसार 50 मिमी आकार की मशीन कुचल पत्थर गिट्टी की आपूर्ति और अतुल मेगा में हॉपर में गिट्टी की लोडिंग डिपो मात्रा=1,00,000cu. लगभग। कार्य की लागत: 9,28,41,000/–. ईएमडी: 6,14,200/–. क्रम संख्या: 2. ई–निविदा सूचना संख्या- बीसीटी/24–25/137 दिनांक 13.08.2024। कार्य और स्थान- विरार – जोरावसन अनुभाग- एडीईएन/बीएल के अधिकार क्षेत्र के तहत डूंगरी–संजान अनुभाग में मौजूदा कर्मचारी क्वार्टरों और अन्य सेवा भवनों की मरम्मत और पेंटिंग। लगभग। कार्य की लागत: ₹2,97,69,165.60. ईएमडी: ₹2,98,900/–। दोनों निविदाएं जमा करने की तिथि और समय- 10.09.2024, 15.00 बजे तक। दोनों निविदाओं को खोलने की तिथि और समय- 10.09.2024 को 15:30 बजे। विवरण के लिए कृपया www.ireps.gov.in पर जाएं। 0456

हमेंलाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे - वड़ोदरा मण्डल

"विज्ञापन", "पे एंड यूज़", "पे और पार्क" और खानपान" अनुबंधों के लिए ई-नीलामी

उपरोक्त के संदर्भ में, "विज्ञापन", "पे एंड यूज़", "पे और पार्क" और खानपान" अनुबंधों के लिए ई-नीलामी 29.08.2024 को आयोजित की जाएगी। सूची पहले ही www.ireps.gov.in वेबसाइट पर प्रकाशित की जा चुकी है। विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं:

कैटलॉग संख्या	अनुबंध के प्रकार	लॉट संख्या	अनुबंध की अवधि
ADVT-BRC-090824 (नीलामी समय 11: 00 बजे.)	विज्ञापन	ADVT-EFF-132142-24-2 (विज्ञापन-ट्रेन का बाहरी भाग (फुल फेस)	05 वर्ष
		ADVT-BRC-BRC-OH-278-24-1 (विज्ञापन - आउट ऑफ होम)	05 वर्ष
		ADVT-BRC-BRC-OH-288-24-1 (विज्ञापन - आउट ऑफ होम)	05 वर्ष
		ADVT-BRC-BRC-OSN-259-24-1 (विज्ञापन - स्टेशन परिसर में (नोन-डिजिटल)	05 वर्ष
		ADVT-IntExt-86019-24-2 (विज्ञापन-ट्रेन का आंतरिक और बाहरी भाग)	05 वर्ष
		MSS-BRC-BRC-MCK-20-24-1 (विविध-स्थैतिक-सेवाएं डिजिटल मोबाइल चार्जिंग कियोस्क)	03 वर्ष
C331-PnU-290824 (नीलामी समय 11: 00 बजे.)	पे एंड यूज़	PnU-BRC-MHD-Toi-11-24-3 (पे एंड यूज़ - शौचालय)	03 वर्ष
		PnU-BRC-KIM-Toi-2-24-3 (पे एंड यूज़ - शौचालय)	03 वर्ष
		PnU-BRC-KSB-Toi-3-24-3 (पे एंड यूज़ - शौचालय)	03 वर्ष
		PnU-BRC-EKNR-Toi-13-24-3 (पे एंड यूज़ - शौचालय)	03 वर्ष
		PnU-BRC-MYG-Toi-6-24-3 (पे एंड यूज़ - शौचालय)	03 वर्ष
		PnU-BRC-PLJ-Toi-5-24-3 (पे एंड यूज़ - शौचालय)	03 वर्ष
C481-PRKG-2908 (नीलामी समय 11: 00 बजे.)	पार्किंग	PARKING-BRC-MHD-TW-19-24-1 (टू व्हीलर वाहन पार्किंग)	03 वर्ष
		PARKING-BRC-VS-MX-5-24-3 (पार्किंग मिश्रित)	03 वर्ष
CATG-BRC-2908 (नीलामी समय 10:00 बजे.)	खानपान एमपीएस	MPS-BRC-BRC-MPS-1-24-1 (एमपीएस-मल्टी पर्पस स्टॉल)	05 वर्ष
		MPS-BRC-EKNR-MPS-3-24-1 (एमपीएस-मल्टी पर्पस स्टॉल)	05 वर्ष
		MPS-BRC-MHD-MPS-2-24-1 (एमपीएस-मल्टी पर्पस स्टॉल)	05 वर्ष

159

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

मालिक, मुद्रक-प्रकाशक व सम्पादक : लक्ष्मीचन्द जी. अग्रवाल द्वारा ब्रिजाशा ऑफसेट, सरसपुर, अहमदाबाद में मुद्रित करवाकर, स्वेतप्रित बिल्डिंग, खासवाड़ी, बहुचराजी रोड़, वड़ोदरा से प्रकाशित किया। प्रातःकालीन E-mail: janhitaishi@yahoo.co.in Mob.9375504122 R.N.I. 64278/96